नई दिल्ली । सोमवार , 02 फरवरी, 2026
फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082,
वर्ष :12, अंक :29 । मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
# विश्व केसरी
नई दिल्ली संस्करण
vishwakesari.com
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415
सिर्फ पत्रकारिता...

@ खेल ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन कर्लिंग टाइटल..
@ विचार तेल के खेल में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता..
@ व्यापार एसटीटी में बढ़ोतरी से निराश बाजार...

## बजट 2026-27 का केंद्र बिंदु ग्रोथ, सरकार का मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर बड़ा फोकस : एक्सपर्ट्स

**एजेंसी ■ नई दिल्ली**

केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट लोकलुभावन नहीं, बल्कि लंबी अवधि की आर्थिक मजबूती, निवेश और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इस बजट में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है।

पीएचडीसीसीआई के इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी चेयरमैन अशोक बत्रा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बजट 2026-27 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका केंद्र बिंदु ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि यह बजट पॉपुलिज्म से दूर रहकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म विजन पर आधारित है। एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड इक्विटी सपोर्ट के जरिए छोटे उद्योगों को मजबूती देगा। इससे एमएसएमई न केवल घरेलू चुनौतियों से निपट पाएंगे, बल्कि यूके और ईयू जैसे देशों के साथ हुए एफटीए का लाभ उठाकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि सीपीएसयू को भुगतान व्यवस्था के दायरे में लाने से एमएसएमई की लिक्विडिटी समस्या काफी हद तक खत्म होगी और उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा, जिससे वे अपने कारोबार पर बेहतर फोकस कर सकेंगे।

वोल्वो ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और एमडी कमल बाली ने बजट को प्रेरणादायक और सकारात्मक बताया। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती मैन्युफैक्चरिंग रही है, जिसकी हिस्सेदारी अभी जीडीपी में करीब 14 प्रतिशत है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर-चाहे वह सनराइज इंडस्ट्री हो या पारंपरिक उद्योग-दोनों पर मजबूत फोकस दिखता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के 25 प्रतिशत तक ले जाया गया, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट रोजगार, निर्यात और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर साफ दिखेगा।

केएमजी वेंचर्स के डायरेक्टर अमन कंसल ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है, खासकर बायोफार्मा, केमिकल पाथ और क्लस्टर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में। इन सेक्टर्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, पीएम गतिशक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

एसोचैम जेएंडके काउंसिल के सदस्य शिवांग गुप्ता ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जो मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर, खासकर माउंटेन ट्रेल्स और हाइकिंग इंडस्ट्री, को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में 10,000 से 20,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन करने का प्रस्ताव रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम है। कनेक्टिविटी सुधार पर भी सरकार का फोकस सराहनीय है। इसके साथ ही एसोचैम जेएंडके काउंसिल के चेयरमैन मानिक बत्रा ने बजट को संतुलित और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जीडीपी में करीब 30 प्रतिशत योगदान देता है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, 2,000 करोड़ का टॉप-अप और बेहतर ग्लोबल मार्केट लिंकज से यह सेक्टर और मजबूत होगा। बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ और सेमीकंडक्टर मिशन-2 के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि नई फ्रेट कॉरिडोर, सात रेल कॉरिडोर, जलमार्ग विकास और 2,000 पुराने इंडस्ट्रियल जोन के पुनरुद्धार से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार दोनों को गति मिलेगी।

बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई दवाओं पर टैक्स में कटौती, आयुष फार्मेसी को अपग्रेड करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। टूरिज्म सेक्टर में स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने, 10-15 पुरातात्विक स्थलों के विकास और 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को आईआईएम के सहयोग से ट्रेन करने का प्रस्ताव रोजगार और जीडीपी दोनों को मजबूती देगा।

## 'छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा, भविष्य की मजबूत नींव', पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया

**एजेंसी ■ नई दिल्ली**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026-27 पेश किया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने तमाम सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसी बीच, बजट को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दिखाता है। यह सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है।

उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। ये विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। मित्रों, भारत जिस सुधार की रफ्तार पर आज चल रहा है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। इस बजट से यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बजट से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि यह बजट भरोसे पर आधारित गवर्नेंस और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को दिखाता है।

यह एक खास बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने को प्राथमिकता देता है, साथ ही ज्यादा पूंजीगत खर्च और मजबूत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि विश्व के एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक भागीदार और विश्वसनीय गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जो बड़े-बड़े व्यापार सौदे भारत ने किए हैं, जिसका मुख्य लाभ भारत के युवाओं को मिला, भारत के लघु और मध्यम उद्योग के लोगों को मिला, इस दिशा में बजट में बड़े-बड़े कदम दिए गए हैं।

## भारत ने बांग्लादेश की वित्तीय सहायता में की कटौती, इन देशों के लिए बढ़ाया अपना बजट

**एजेंसी ■ मुंबई**

**नई दिल्ली ।** भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट 2026-27 पेश किया है। ऐसा करने वाली निर्मला सीतारमण पहली विदेश मंत्री बन गईं। नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) के तहत विदेशी सहायता के लिए बजट 2026-27 के लिए विदेश मंत्रालय को 22118.97 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये आंकड़ा 20516.61 करोड़ रुपए था। पिछले साल की तुलना में भारत ने इस साल दूसरे देशों के लिए बजट में बड़े बदलाव किए हैं। भारत ने कई देशों के लिए बजट बढ़ाया है, तो कुछ देशों के लिए वित्तीय सहायता घटाई भी है।

बजट 2026-27 में भारत ने अपने सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार भूटान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2,288.55 करोड़ रुपए कर दी है। यह दोनों देशों के बीच, खासकर हाइड्रोपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरिया में हमेशा रहने वाले खास रिश्तों को दिखाता है।

अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 50 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए की गई है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में मानवीय मदद के लिए राहत संबंधित कार्य करता रहा है। ऐसे में यह बजट मानवीय और विकास में मदद के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट का संकेत है।

इसके अलावा नेपाल को 800 करोड़ रुपए मिले हैं, जो 100 करोड़ रुपए ज्यादा है। वहीं, श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 100 करोड़ ज्यादा है। तूफान दित्वाह से निपटने के लिए हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लिए वित्तीय सहायता भेजी थी। ऐसे में ये बजट स्वाभाविक रूप से सुधार और जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया गया है। इस लिस्ट में मंगोलिया का नाम भी शामिल है, जहां वित्तीय सहायता के लिए पहले के 5 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया गया है। इसके साथ ही मॉरिशस के लिए वित्तीय सहायता 50 करोड़ से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया। सेशेल्स के लिए पिछले साल की तरह बजट 19 करोड़ रुपए ही है।

भारत ने बांग्लादेश के लिए वित्तीय सहायता में बड़ी कटौती की है। बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है।

## क्यूबा में छाए मानवीय संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम

**नई दिल्ली ।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर क्यूबा के अधिकारी मानवीय संकट से बचना चाहते हैं, तो उन्हें वॉशिंगटन के साथ एक समझौता करना होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह धमकी तब आई है, जब उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में क्यूबा को तेल बेचने वाले किसी भी देश के सामान पर टैरिफ लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया। ट्रंप के इस फैसले के बाद से क्यूबा के खिलाफ 1960 के दशक से चली आ रही रोक और मजबूत हो गई। क्यूबा के लिए वेनेजुएला तेल का मुख्य स्रोत था। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की और तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ले आया गया। मेक्सिको ने हाल के हफ्तों में क्यूबा को तेल की डिलीवरी बढ़ा दी है। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा कर सकता है, जिसका सीधा असर क्यूबा के लोगों के लिए अस्पतालों, फूड सप्लाई और दूसरी बेसिक सेवाओं पर पड़ेगा।

शनिवार को एयर फोर्स वन में मीडिया ने राष्ट्रपति शीनबाम की ओर से किए गए इस टिप्पणी को लेकर सवाल किया, तो ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, यह मानवीय संकट होना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि वे शायद हमारे पास आएंगे और एक डील करना चाहेंगे। तो, क्यूबा फिर से आजाद हो जाएगा।

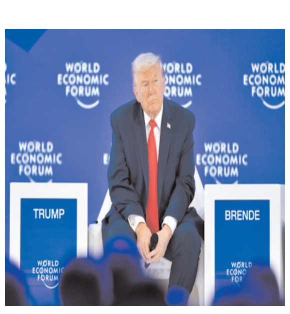


उन्होंने कहा, 'क्यूबा के हालात बहुत खराब हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके पास तेल नहीं है। वे वेनेजुएला के पैसे और तेल पर जीते थे, और अब उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि दोनों पक्ष एक डील कर लेंगे और वॉशिंगटन हवाना के प्रति दयालु होगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वह क्यूबा सरकार से कौन सी खास छूट चाहते हैं, बस इतना कहा कि अमेरिका में अभी बहुत से लोग हैं, जो क्यूबा वापस जाना चाहेंगे और हम इस पर काम करना चाहेंगे।

## 'विकसित भारत बजट' एक ऐसे देश के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो : अमित शाह

**नई दिल्ली ।** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आम बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा उनकी टीम का धन्यवाद और साधुवाद किया।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो।

मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण और अगले 25 वर्षों के रोडमैप को दर्शाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर भारतवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन।

विकसित भारत बजट भारत को एक नई पहचान देने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपनी ताकत पर अडिग भरोसा रखता है और

एक उभरते आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। कोविड के बाद पीएम मोदी की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। विकसित भारत बजट इस गति को और तेज करता है और भारत को वैश्विक मंच पर सबसे आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करता है, चाहे वह पारंपरिक क्षेत्र हों या नए युग के उद्योग।

बजट में पशुधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने, वेटरनरी सेंटरों और ट्रेनिंग सेंटरों के विस्तार से पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देने, 500 सरोवरों के विकास से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने जैसे निर्णय मोदी सरकार के किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में विकसित भारत बजट में 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना' की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बुनकरों, किसानों तथा हथकरघा उद्योग को नया संबल प्राप्त होगा। तटीय क्षेत्रों में कोकोनट प्रमोशन स्कीम से 3 करोड़ किसानों को लाभ, काजू-कोको के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा व चंदन संरक्षण का निर्णय यह दर्शाता है कि मोदी जी किसानों की समृद्धि और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बजट भारत में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। आज सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो प्रमुख आर्थिक और जनसंख्या केंद्रों के बीच यात्रा समय कम करके शहरों को तेजी से जोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत बजट के शानदार मील के पत्थर पर बधाई देता हूं, जो मोदी सरकार की विकास और प्रगति को वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। इस बजट ने राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य पूरा किया है।

बजट पीएम मोदी के विजन 'फ्यूचर रेडी भारत' को तेजी देता है, जहां विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के रूप में आवंटित किए गए हैं। नए रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय जलमार्ग और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच बनाना रोजगार बढ़ावा देगा और भारत की महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई तक ले जाएगा।

## बजट 2026-27 में टैक्स रेवेन्यू में 8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान, 44.04 लाख करोड़ रुपए कमाई की उम्मीद

**नई दिल्ली ।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में सरकार ने कुल सकल कर राजस्व (ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू) 44.04 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 8 प्रतिशत ज्यादा है।

डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स शामिल हैं, से 26.97 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जो कुल टैक्स आमदनी का करीब 61.2 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से 17.07 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई है।

बजट अनुमान 2026-27 में टैक्स और जीडीपी का अनुपात 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह बजट सोलहवें वित्त आयोग (16वां फाइनेंस कमीशन) की सिफारिशों के लागू होने का पहला साल भी है। वित्त आयोग ने राज्यों को मिलने वाले टैक्स हिस्से को 41 प्रतिशत पर ही बनाए रखने की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार को मिलने वाली शुद्ध टैक्स आमदनी (नेट टू सेंटर) 28.67 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके अलावा, गैर-कर राजस्व (नॉन-टैक्स रेवेन्यू-एनटीआर) 6.66 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। वहीं, केंद्र सरकार की कुल रेवेन्यू रिसीट, जिसमें टैक्स और नॉन-टैक्स दोनों शामिल हैं, 35.33 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह राशि 2025-26 के मुकाबले करीब 5.7 प्रतिशत ज्यादा है। बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का करीब 13.6 प्रतिशत है और पिछले साल (49.65 लाख करोड़ रुपए) की तुलना में 7.7 प्रतिशत ज्यादा है।

वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए 12.22 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है। इसमें राज्यों को दिए जाने वाले विशेष ऋण के रूप में 2.0 लाख करोड़ रुपए की सहायता भी शामिल है।

केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत खर्च, सरकार के अपने खर्च और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को मिलाकर तय किया जाता है। यह निवेश देश की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।

## संक्षिप्त खबर

### दिल्ली : नितिन नवीन ने गुरु रविदास मंदिर में की पूजा-अर्चना

**नई दिल्ली।** संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्रामधाम मंदिर में पूजा-अर्चना की। नितिन नवीन और वीरेंद्र सचदेवा ने स्थानीय महिलाओं द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में भी भाग लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंदिर की आगंतुक पुस्तिका में संत श्री रविदास समाज के लिए शुभकामना संदेश भी लिखा। देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन जयंती पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय संत परंपरा में गुरु रविदास भक्ति, समानता और मानवीय मूल्यों के अग्रदूत थे। गुरु रविदास ने अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से जाति भेद, सामाजिक असमानता और अन्याय का विरोध किया तथा प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक समरसता और सद्भावना का जो दीप जलाया, वह सदैव देश को मार्गदर्शन देता रहेगा। मंदिर प्रबंधन समिति और दिल्ली भाजपा के नेताओं ने नितिन नवीन का स्वागत और सम्मान किया तथा उन्हें संत श्री रविदास की एक छोटी स्मृति प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में नितिन नवीन और वीरेंद्र सचदेवा के साथ राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा एससी मोर्चा अध्यक्ष लालसिंह आर्य, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मयूख, दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीन शंकर कपूर, करोल बाग जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, पूर्व सांसद अनिता आर्य और भाजपा नेता विनय रावत, रविंद्र गुप्ता, विक्रम मित्तल, परीक्षित बागरी और मोहन लाल गिहारा भी मौजूद रहे। इससे पहले 20 जनवरी को नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभालने से पहले कई धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा-अर्चना की थी। उन्होंने सुबह झंडेवाला मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर और गोल मार्केट के पास मंदिर मार्ग पर स्थित प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर में भी पूजा की।

### असमिया पहचान की रक्षा की लड़ाई जनता को ही लड़नी होगी: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

**गुवाहाटी।** असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को असमिया समाज के सामने खड़े होते पहचान संकट को रेखांकित करते हुए कहा कि अब असमिया पहचान की रक्षा की लड़ाई का नेतृत्व जनता को स्वयं करना होगा। उन्होंने चिंता जताई कि महावीर चिलाराय और महाराज नरनारायण के शासन वाले ऐतिहासिक क्षेत्रों में असमिया लोग अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं।दरांग जिले के पिपोरा दुकान में आयोजित 516वें बिस्वा महावीर चिलाराय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने चिलाराय-नरनारायण क्षेत्र के बड़े हिस्सों में आक्रामक अतिक्रमण और जनसांख्यिकीय बदलावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र रहे इलाकों में स्वदेशी समुदाय की उपस्थिति लगातार कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'असमिया समाज आज पहचान के संकट का सामना कर रहा है। जिन क्षेत्रों पर कभी चिलाराय और नरनारायण का शासन था, वहां आज असमिया लोग अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं।' उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी विरासत और पहचान की रक्षा के लिए केवल सरकार पर निर्भर न रहें। सरमा ने कहा कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन यह लड़ाई केवल प्रशासनिक कदमों से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने कहा, 'सरकार पहल कर सकती है, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व जनता को ही करना होगा।' उन्होंने गरुखुटी भूमि पुनःप्राप्ति अभियान को एक लंबी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत बताया। कोच राजबोंगशी समुदाय की स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अविभाजित गोलपाड़ा जिले में यह समुदाय अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि पूर्व कोच साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर बांग्लादेश से आए प्रवासियों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है। महावीर चिलाराय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरमा ने उन्हें न केवल एक निर्भीक सेनानायक बल्कि असम के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की नींव रखने वाला दूरदर्शी वास्तुकार बताया। उन्होंने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के चिलाराय के संरक्षण से एक सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात हुआ और 'वृंदावनी वस्त्र' जैसी अद्वितीय कृति उसी युग की स्थायी पहचान है। मुख्यमंत्री ने महावीर चिलाराय और लचित बरफूकन को प्रेरणा के शाश्वत स्रोत बताते हुए कहा कि उनके साहस और बलिदान से ही असमिया समाज को आज की चुनौतियों से पार पाकर अपनी सभ्यतागत विरासत की रक्षा करनी चाहिए।

# केंद्रीय बजट दूरदर्शी और ऐतिहासिक, पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प : नायब सिंह सैनी

**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट दूरदर्शी और ऐतिहासिक है, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने इस बजट को कल्याणकारी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट के तीन मुख्य दृष्टिकोण गति, क्षमता और समावेशी विकास हैं। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 2026-27 में सरकार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, '2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और नगर-आर्थिक क्षेत्रों का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और अवसंरचना-केंद्रित राज्य की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।' मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बजट में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हरियाणा के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से राखीगढ़ी जैसे हरियाणा के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा, 'एआई और क्वांटम मिशन में निवेश से गुरुग्राम की वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थिति और मजबूत होगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा, 'कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि और डिजिटल कृषि मिशन पर जोर देना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हैं। बजट में देश भर में बड़े कपड़ा पार्क और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।' मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।' राज्य के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट को दूरदर्शिता, संतुलन और समावेशी विकास की भावना के साथ तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह बजट देश को 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर 'बुलेट ट्रेन की गति' से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बजट में किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवाओं और महिलाओं के हितों का उचित ध्यान रखा गया है। बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

## बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बनाए गए 1762 एग्जाम सेंटर

**पटना।** बिहार में सोमवार से 12वीं यानी इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कुल 13.17 लाख से अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। 13 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा के कदाचारमुक्त कराने के लिए बीएसईबी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ? ?इस परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी समेत तमाम प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक जिला में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां केवल छात्राएं शामिल होंगी। ?दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। पाली का समय सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक रखा गया है, जबकि दूसरी पाली का समय दोपहर 2:00 से 5:15 बजे तक रखा गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पहले दिन पहली पाली में जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में कला संकाय और वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा होनी है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले मुख्य गेट बंद किया जाएगा। देर से पहुंचने या जबरन प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित किए गए हैं। ? ?बोर्ड द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर बिलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी केंद्र में जबरदस्ती या अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे।

## कृति सेनन ने मनीष मल्होत्रा के लिए लिखा खास पोस्ट, खूबसूरत आउटफिट्स पर जताया आभार

**मुंबई।** बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने बीते महीने अपनी बहन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन की शादी धूम-धाम से सेलिब्रेट की थी। शादी के बाद अभिनेत्री लगातार अलग-अलग फंक्शन से जुड़ी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। उन्होंने अपनी बहन की विदाई को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने इंडस्ट्री के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए एक थैंक्यू पोस्ट किया है। कृति सेनन और उनके पूरे परिवार ने नुपूर की शादी में जितनी भी इंडियन ड्रेसेज पहनी थीं, उन्हें मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। नुपूर की शादी का लहंगा और उनके माता-पिता समेत कृति की ड्रेस भी मनीष ने खास तौर पर डिजाइन किए थे। अब कृति ने इतनी खूबसूरत इंडियन ड्रेसेज और शादी को यादगार बनाने के लिए डिजाइनर का धन्यवाद किया है। उन्होंने परिवार के साथ फोटोज पोस्ट कर लिखा, 'मेरे खास दोस्त मनीष मल्होत्रा के लिए खास पोस्ट। शादी के लिए मेरे पूरे परिवार को इतने खूबसूरत ढंग से सजाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।' उन्होंने लिखा, 'आपने सभी के लुक को इतने प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से कस्टमाइज किया कि दुल्हन से लेकर मेरे माता-पिता तक, जो पहली बार मनीष मल्होत्रा ??की ड्रेस पहनकर बेहद खुश थे, सभी खुश और सहज महसूस कर रहे थे। सबके चेहरों पर दिख रही खुशी सब कुछ बयां कर रही है। हमारे खास दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बहन नुपूर की शादी के दिन कृति ने ऑफ व्हाइट और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर पैच वर्क से लेकर बारीक कढ़ाई की गई थी, जबकि अभिनेत्री की मां ने पिंक और गोल्डन कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी। वहीं, दुल्हन नुपूर का लहंगा पिंक और रेड दोनों शेड्स के साथ था। सभी इंडियन ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थीं। नुपूर सेनन से पहले मनीष मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी और कैटरीना कैफ तक के लिए आउटफिट डिजाइन कर चुके हैं। उन्होंने कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के लिए शादी का आउटफिट डिजाइन किया था।

## गरीब और किसान विरोधी है केंद्रीय बजट : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

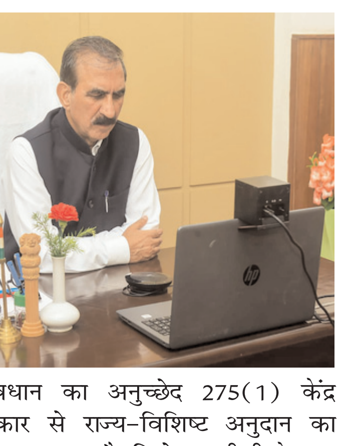

**शिमला।** केंद्रीय बजट 2026-27 पर निराशा जताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को इसे गरीब विरोधी और किसान विरोधी बजट बताया। उन्होंने कहा कि 'यह समाज के अहम वर्गों के हितों की अनदेखी करता है।' मुख्यमंत्री ने बजट को असमान बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की चिंताओं और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने हाल ही में पेश की गई 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवीआई) की रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई।

मुख्यमंत्री ने बार-बार अनुरोध, विस्तृत ज्ञापन और तकनीकी प्रस्तुतियां देने के बावजूद आयोग द्वारा राज्य के लिए सार्थक राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) प्रदान करने में विफलता पर निराशा व्यक्त की। इसके अलावा, वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सहित छोटे राज्यों के लिए आरडीजी की सिफारिश नहीं की है, जिसे उन्होंने बहुत निराशाजनक फैसला बताया और इसे अन्याय करार दिया, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 275(1) केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट अनुदान का प्रावधान करता है, जिसे आरडीजी के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग तक, ये अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को नियमित रूप से प्रदान किए जाते थे।

`हालांकि, पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत, लगभग 37,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 14वें वित्त आयोग के पूरा होने के बाद, जब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जमा करने में देरी हुई, तो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 11,431 करोड़ रुपए की सहायता अभी भी प्रदान की गई थी।

मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, 'यह दुखद है कि इस चूक में संरचनात्मक वित्तीय बाधाओं को नजरअंदाज किया गया है, जिसमें लगभग 67 प्रतिशत उच्च वन और पारिस्थितिक आवरण, पहाड़ी इलाकों में सेवा वितरण की प्रति व्यक्ति उच्च लागत और हाल के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने वाली बार-बार प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं।'

हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी-विशिष्ट प्राथमिकताओं जैसे जलविद्युत विकास, इको-टूरिज्म, सड़क और रेल कनेक्टिविटी और जीएसटी लागू होने से होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे के लिए लक्षित समर्थन की उम्मीद थी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पर्याप्त आरडीजी की अनुपस्थिति हिमाचल प्रदेश की आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और भविष्य के विकास में निवेश करने की क्षमता को सीमित करेगी, जिससे संभावित रूप से सेवा वितरण और बढ़ते कर्ज के बीच कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

## जम्मू-कश्मीर: एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जम्मू में ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया

**जम्मू।** जम्मू-कश्मीर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने रविवार को बताया कि उसने जम्मू शहर में 18 किलोग्राम अफीम के भूसे के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जम्मू के सिधरा पंजतीर्थी लिंक रोड में नाकाबंदी अभियान के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। विशिष्ट सूचना के आधार पर, एएनटीएफ की एक टीम ने सिधरा पंजतीर्थी लिंक रोड पर एक ऑल्टो कार को रोका। वाहन की गहन तलाशी के दौरान 18 किलोग्राम से अधिक अफीम के भूसे जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजौरी के गुंडा खवास निवासी किरपाल सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी कश्मीर से जम्मू में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था ताकि उन्हें इलाके के भोले-भाले युवाओं में अवैध रूप से वितरित किया जा सके।

आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त कर लिया गया है। इस क्रम में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और नशीले पदार्थों के स्रोत और इस नशीले पदार्थों के नेटवर्क में शामिल कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। जम्मू-कश्मीर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और संगठित मादक पदार्थों के गिरोहों को नष्ट करने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ संकल्पित है।

जनता से अनुरोध है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें।

## यह बजट भी राज्य के लिए निराशाजनक साबित हुआ: कर्नाटक मंत्री एमबी पाटिल

**बेंगलुरु।** कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बेंगलुरु-हैदराबाद और बेंगलुरु-चेन्नई के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन इससे सीमित लाभ ही मिलेगा। वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के केंद्रीय बजट पर मीडिया से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इसके बजाय, बेंगलुरु और पुणे के बीच इसी तरह का कॉरिडोर शुरू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के सांसदों को इस मुद्दे को सामूहिक रूप से और निष्पक्ष तरीके से उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि घोषित दोनों मार्गों पर ट्रेनें कर्नाटक के भीतर 100 किलोमीटर तक भी नहीं चलेंगी।

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है।

पाटिल ने कहा कि राज्य ने मांग की थी कि ऊपरी कृष्णा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए और ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए पहले से घोषित 5,600 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जाए। हालांकि, बजट में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, बजट में कृषि समुदाय को सहायता देने के उद्देश्य से एक भी योजना शामिल नहीं है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह, यह बजट भी राज्य के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने और पांच क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के प्रस्ताव कर्नाटक की 'क्वीन' सिटी अवधारणा से प्रभावित हैं।

मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य ने दो रक्षा गलियारा परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी मांगी थी।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मजबूत एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए इन्हें बजट में जगह मिलनी चाहिए थी। हालांकि, वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव का जिक्र तक नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि 'क्वीन' सिटी परियोजना कुल 5,000 एकड़ क्षेत्र में लागू की जाएगी। ह्यउन्होंने कहा कि पहले चरण में, 2,000 एकड़ भूमि पर इसका विकास किया जा रहा है, और वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अंतर्गत अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालयों के परिसर, गुणवत्तापूर्ण अस्पताल और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

## आम बजट से छत्तीसगढ़ को सीधा लाभ मिलेगा: विष्णुदेव साय

**नई दिल्ली।** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बजट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों, आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा 'सबका साथ, सबका विकास' सुनिश्चित करना, को केंद्र में रखा गया है। सीएम ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने

के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे।

# सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन आवश्यक : राज्यपाल डेका

**राज्यपाल ने संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन किया**

**रायपुर ।** पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों के सहयोग से संरक्षण क्षमता महोत्सव 'सक्षम 2025-26' का आयोजन 1 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को राज्यपाल रमेन डेका ने किया।

इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि सक्षम एक अत्यंत महत्वपूर्ण जन-जागरूकता कार्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभ्यता के विकास के साथ मानव को ऊर्जा के अनेक साधन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से प्रकृति और भावी पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।अतिरिक्त दोहन से नुकसान होता है, इसलिए सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी हमारे मूलभूत अधिकार हैं। नदियों और पेड़ों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में सुरक्षित रखना चाहिए। राज्यपाल ने कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग और माइक्रो-प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि माइक्रो-प्लास्टिक का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और यह अब माता के दूध में भी पाया जा रहा है। प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान मनुष्य स्वयं पहुंचा रहा है, इसलिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि जागरूकता केवल बोलने से नहीं आती, बल्कि इसे हमारी दिनचर्या और आदतों का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने बिजली के दुरुपयोग को रोकने और हर स्तर पर ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के सीमित होने पर हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके लिए ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाना होगा। अत्यधिक पेट्रोल ,डीजल उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है।

उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का आह्वान करते हुए जल संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। बड़े किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण करना चाहिए, जिससे सामूहिक लाभ हो सके। साथ ही पुराने तालाबों और डबरियों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और समाज के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है।

कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन नितिन चव्हाण राज्य स्तरीय समन्वयक एवं मंडल प्रमुख इंडियन ऑयल द्वारा दिया गया। आभार प्रदर्शन हिंदुस्तान पैट्रोलियम के नितिन श्रीवास्तव ने किया।

इस अवसर पर इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा गेल के वरिष्ठ अधिकारी गण कर्मचारी, विद्यार्थी तथा नागरिक उपस्थित थे।

# औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बजट : लखन लाल देवांगन

**रायपुर ।** वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।देवांगन ने कहा कि बजट में MSME और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा।उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान से स्थानीय इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से डिजिटल उद्योग, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। वहीं, बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा। छोटे किसानों की उद्यमशीलता, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और 500 अमृत जलाशयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।देवांगन ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। कुल मिलाकर यह बजट औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और समग्र विकास के माध्यम से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।

# धान खरीदी और जप्ती मामले में प्रदेश में पहले पायदान पर रहा महासमुंद जिला

**महासमुंद।** खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले में स्थापित 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 10,00,187.16 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक रही। शासन द्वारा जिले के लिए 11,93,570.00 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले में 11,04,273.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.43 प्रतिशत कम धान खरीदी दर्ज की गई। इस वर्ष धान खरीदी हेतु जिले में 1,60,118 किसान पंजीकृत थे, जिनमें से 1,48,418 किसान (92.69 प्रतिशत) ने खरीदी अवधि के दौरान अपना धान विक्रय किया, जो राज्य के औसत 91.22 प्रतिशत से अधिक है।

# बजट 2026 समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : लक्ष्मी राजवाड़े

**रायपुर ।** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे 'समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला जनहितैषी बजट' बताया है।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता को समान रूप से प्राथमिकता देकर देश के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान की गई है।

उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण से छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी। वहीं लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार से महिलाओं को आजीविका से उद्यमिता की ओर अग्रसर होने का सशक्त अवसर मिलेगा।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने से महिलाओं के साथ-साथ युवाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। यह बजट सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है।

राजवाड़े ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विजन को साकार करने वाला है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश को तेजी से अग्रसर करेगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की

# स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देना वाला है बजट : मंत्री जायसवाल

**रायपुर।** केंद्रीय बजट 2026 को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बजट देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लिए गए दूरदर्शी निर्णयों पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में औषधि प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना का निर्णय दवा निर्माण और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। आयुष सेक्टर को सशक्त करते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। बजट में केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्यों को सहयोग देकर देश में पांच रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है।

# रायपुर में भाजपा सहयोग केंद्र फिर होगा शुरू, चार दिन चार मंत्री करेंगे समस्या निराकरण

**रायपुर ।** भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके क्षेत्रों की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों को बारी-बारी से ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में बैठक कर समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के लिए कहा गया था। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2024 में की गई थी, जिसके तहत मंत्री स्वयं बैठकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनते रहे। हालांकि, एक बार शुरू होने के बाद सहयोग केंद्र बंद हो जाने से कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करना पड़ा। बीते वर्ष अक्टूबर में इसे पुनः प्रारंभ किया गया, लेकिन दीपावली को देखते हुए यह व्यवस्था महज दो सप्ताह ही चल पाई। इस दौरान मंत्रियों के समक्ष एक हजार से अधिक समस्याएं और मांगें सामने आईं, जिनमें से लगभग आधी समस्याओं का तत्काल समाधान कर दिया गया था।

# किसान मेले में अखिल जैन ने गौ आधारित कृषि का दिया प्रशिक्षण

**रायपुर ।** छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा दुर्ग जिले के कुम्हारी में आयोजित दो दिवसीय किसान मेले का शनिवार को समापन हो गया। इस मेले में खैरागढ़ मनोहर गौशाला का स्टॉल लगाया गया। जहां ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन (पदम डाकलिया) ने किसानों को गौ आधारित कृषि का प्रशिक्षण दिया। साथ ही मेले में पहुंचे केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को गोबर की माला पहनाकर गोबर से बने दीये और फसल अमृत की बोतल भेंट की।

डॉ. जैन से प्रशिक्षण लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने जैविक खेती अपनाने का संकल्प लिया।

# आईसीएआर-एनआईबीएसएम रायपुर में सचिव डेयर एवं महानिदेशक आईसीएआर का दौरा

**रायपुर ।** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (आईसीएआर-एनआईबीएसएम), रायपुर को सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) डॉ. एम.एल. जाट के आधिकारिक दौरे की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके साथ उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. डी.के. यादव तथा उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. राजबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

आगंतुक अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉ. पी.के. राय ने संयुक्त निदेशकों, वरिष्ठ वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में किया।

इस अवसर पर डॉ. पी.के. राय ने संस्थान के उद्देश्यों, चल रही अनुसंधान गतिविधियों और फसलों में जैविक तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। अतिथियों ने संस्थान की प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और प्रायोगिक क्षेत्रों का अवलोकन भी किया। डॉ. एम.एल. जाट ने वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए बदलते जलवायु परिदृश्य में उभरते जैविक तनावों से निपटने के लिए नवाचारी और अंतर्विषयक अनुसंधान पर जोर दिया।

उन्होंने सतत कृषि के लिए संस्थान के योगदान की सराहना करते हुए किसान-उन्मुख एवं व्यवहारिक अनुसंधान को और मजबूत करने का आह्वान किया।ह्य

# ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर सरसों की खेती–प्रगतिशील कृषक कमलेश साहू की दूरदर्शी सोच बनी प्रेरणा

**बेमेतरा ।** जिले के ग्राम पथर्रा निवासी प्रगतिशील कृषक कमलेश साहू ने इस वर्ष खेती में एक सराहनीय और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन धान की पारंपरिक खेती के स्थान पर सरसों की फसल को अपनाया है। लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में सरसों की खेती कर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि परिस्थितियों और संसाधनों के अनुरूप फसल चयन से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

**परिवर्तन के पीछे की सोच**

श्री साहू ने बताया कि ग्रीष्मकालीन धान की खेती में अत्यधिक पानी, श्रम और लागत की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैकल्पिक फसल के रूप में सरसों को चुना। सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है, जो कम पानी, कम समय और अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार हो जाती है। कृषि विभाग द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी, मार्गदर्शन एवं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया। वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया फसल प्रबंधन श्री साहू द्वारा सरसों की खेती में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है।

# श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु राजिम कुंभ में रेलवे का डिजिटल अभियान, हेल्प डेस्क के जरिए दी जा रही जानकारी

**रायपुर ।** राजिम कुंभ मेला 2026 के भव्य आयोजन को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को रेलवे की डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए 'रेल वन ऐप' के प्रचार-प्रसार का विशेष अभियान शुरू किया गया है, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर जुटने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की जानकारी और सेवाओं तक त्वरित पहुँच प्रदान करना है ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस जागरूकता अभियान का संचालन 01 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने राजिम कुंभ मेला क्षेत्र में प्रतिदिन विशेष सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर वाणिज्य निरीक्षक और संबंधित रेल कर्मचारी तैनात रहेंगे जो यात्रियों को 'रेल वन ऐप' डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाएंगे। साथ ही, वे ऐप के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न तकनीकी सुविधाओं और उनके दैनिक उपयोग के बारे में भी यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। 'रेल वन ऐप' यात्रियों के लिए एक एकीकृत समाधान के रूप में कार्य करता है, जहाँ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग, ट्रेनों की लाइव स्थिति और पीएनआर स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। इसके अतिरिक्त रेल मदद, शिकायत निवारण और स्टेशनों पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का विवरण भी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे का मानना है कि इस डिजिटल साधन के व्यापक उपयोग से कुंभ मेले के दौरान यात्रियों का सफर पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। रायपुर रेल मंडल की इस मुहिम से दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को स्टेशन पर भीड़भाड़ से बचने और अपनी यात्रा की योजना मोबाइल के माध्यम से बनाने में बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है। विभाग का यह प्रयास आधुनिक तकनीक और जनसेवा के तालमेल को दर्शाता है, जिससे न केवल यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा बल्कि रेलवे के परिचालन में भी पारदर्शिता आएगी। यह देखना सुखद है कि प्रशासन तकनीक के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और यात्री सेवा को प्राथमिकता दे रहा है।

# छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मिली नई गति: शिवराज सिंह चौहान

**रायपुर ।** केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रभावी और सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जहां पहले से ही 'धान का कटोरा' के रूप में जाना जाता है, वहीं अब फल और सब्जियों के उत्पादन में हो रही तेज वृद्धि राज्य में कृषि के सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। यह किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। महानदी मंत्रालय भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ को 18 लाख 12 हजार 742 पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 33 हजार अतिरिक्त आवास भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 47,847 किलोमीटर लंबी 10,199 सड़कों को मंजूरी मिली है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है।

# अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

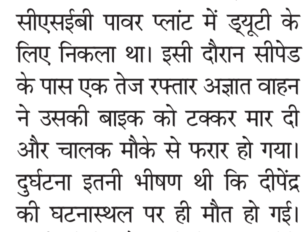


**कोरबा ।** दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत सीपेड के पास सड़क पर एक बाइक सवार युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना तत्काल 112 और दर्री पुलिस को दी। मौके पर पहुंची 112 की टीम ने देखा कि बाइक क्षतिग्रस्त थी और सवार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद शव को जिला मेडिकल कॉलेज के शव कक्ष में सुरक्षित रखवाया गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय दीपेंद्र पटेल के रूप में हुई है, जो कटघोरा थाना क्षेत्र के बरपाली गांव का निवासी था। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को फोन के माध्यम से दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दीपेंद्र पटेल सोमवार रात करीब 10 बजे अपने घर बरपाली से दर्री स्थित सीएसईबी पावर प्लांट में ड्यूटी के लिए निकला था। इसी दौरान सीपेड के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दीपेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके चेहरे और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। परिजनों ने बताया कि दीपेंद्र सीएसईबी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था।

## नशे की लत पाकिस्तान की सामाजिक-आर्थिक संरचना को लगातार कमजोर कर रही है: रिपोर्ट

**इस्लामाबाद।** नशे की लत पाकिस्तान की सामाजिक और आर्थिक संरचना को लगातार कमजोर कर रही है और यह देश के सामने सबसे बड़े चुनौतियों में से एक बनती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में लगभग 67 लाख लोग नियंत्रित ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिसमें सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा कैनबिस है, जबकि हेरोइन की लत से देश में सैकड़ों हजार लोग प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कैनबिस, ओपियोइड्स, कोकेन और विभिन्न सिंथेटिक नारकोटिक्स न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, बल्कि ये सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। दैनिक अखबार पाकिस्तान टुडे में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, 'नशे की लत एक गहरी सामाजिक आपदा बन चुकी है, जो पाकिस्तान की सामाजिक-आर्थिक संरचना को लगातार कमजोर कर रही है और हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन रही है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की युवा आबादी, जो कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत है, विशेष रूप से कमजोर है। उनके सामने साथी दबाव, पारिवारिक कलह, शैक्षिक तनाव, बेरोजगारी और सामाजिक अनिश्चितता जैसी समस्याएं हैं, जो उन्हें विनाशकारी आदतों की ओर धकेलती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को एक मजबूत समाज बनाने, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस, एंटी-नारकोटिक्स फोर्स, कस्टम अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और समुदायिक भागीदारों को मिलकर काम करना होगा ताकि ड्रग्स का दुरुपयोग और अवैध तस्करी कम लाभकारी और कम प्रचलित बन सके। भूगोल के दृष्टिकोण से, गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में अपने रणनीतिक स्थान के कारण, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर नशे के ओपिओइड्स, विशेषकर अफगानिस्तान में उगाए जाने वाले हेरोइन और अफीम, के लिए एक ट्रांजिट और उपभोग क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में, गोल्डन क्रिसेंट ने दक्षिण-पूर्व एशियाई गोल्डन ट्रायंगल (बर्मा, थाईलैंड और लाओस) को वैश्विक नारकोटिक्स उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है।

# द्रमुक और माकपा नेताओं ने बजट को बताया निराशाजनक, केरल-तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप

**चेन्नई।** द्रमुक के संसदीय दल के नेता कनिमोझी और मदुरै से माकपा सांसद सु वेंकटेशन ने रविवार को बजट 2026-27 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि तमिलनाडु और केरल के साथ बजट में 'धोखा' हुआ है, जबकि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने इसे बिना विजन वाला बजट बताया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल सहित कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़े ऐलानों की उम्मीद थी। हालांकि, विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट इन क्षेत्रों के लिए किसी भी सार्थक प्रस्ताव को पेश करने में विफल रहा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कनिमोझी ने बजट को 'बिना बदलाव का निराशाजनक दस्तावेज' करार दिया। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि 'यहां तक कि चुनाव भी केंद्र की भाजपा सरकार को तमिलनाडु की याद दिलाने में नाकाम रहे।' उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान के बावजूद राज्य की जानबूझकर अनदेखी की गई।

माकपा सांसद सु वेंकटेशन ने भी इसी तरह की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट तमिलनाडु के समर्थन के लिए नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने इसे 'निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अब तक का सबसे खराब बजट' बताया और कहा कि यह दक्षिणी राज्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति केंद्र की लगातार उदासीनता को दर्शाता है।

वेंकटेशन ने कहा कि बजट में चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, लेकिन कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल जैसी लंबे समय से लंबित परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने तमिलनाडु और केरल के लिए किसी भी नए बुनियादी ढांचे की घोषणा न होने पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में विशेष आर्थिक कॉरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चिंता व्यक्त की। वेंकटेशन के अनुसार, यह कदम 'उचित प्रतिफल के बिना संसाधनों के दोहन' के समान है और राज्यों के अपने खनिज संसाधनों पर अधिकार को कमजोर करता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने खनिज नीलामी में राज्य सरकारों की शक्तियां सीमित कर दी हैं, जबकि इसके बदले कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया गया। वेंकटेशन ने बजट में आयुर्वेद से जुड़ी पहलों की घोषणा के बावजूद सिद्ध चिकित्सा की अनदेखी और पुरातत्व से जुड़े प्रस्तावों में कीझड़ी (कीलाड़ी) का उल्लेख न होने की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, 'इस बजट में जनकल्याण या विकास के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखती। हर स्तर पर यह बजट भ्रामक है।

'दोनों नेताओं ने दावा किया कि बजट में कोई भी सकारात्मक, जन-केंद्रित कदम नहीं है और केंद्र सरकार पर सहकारी संघवाद की बजाय राजनीतिक नियंत्रण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

## बिहार: मोतिहारी में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

**मोतिहारी।** बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) की पुलिस ने जाली (नकली) नोट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा भारत एवं नेपाल के लाखों रुपए की जाली करेंसी बरामद की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति जाली नोट लेकर नेपाल से बिहार आने वाले हैं। इस सूचना के मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तत्काल रक्सौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित

टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हरैया थाना के बोधी माई मंदिर के पास वाहन जांच अभियान प्रारंभ किया गया।

वाहन चेकिंग के क्रम में बोधी माई मंदिर के पास से संदिग्ध स्थिति में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 18,500 रुपए के भारतीय जाली नोट बरामद हुए। इसके बाद दोनों गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई लोगों के इस नेटवर्क में शामिल होने की जानकारी दी।

इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर आसूचना इकाई टीम के साथ अन्य जिलों में छापेमारी की गई। इसी क्रम में सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 25 लाख नकली नेपाली करेंसी, 1.40 लाख असली नेपाली करेंसी, 22 बंडल सादा पेपर, जाली नोट बनाने का केमिकल तथा अन्य सामाग्री, तीन मोटरसाइकिल एवं एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर इस नेटवर्क के अन्य लोगों का भी पता कर रही है और उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है।

## जवाहर नगर मंडल ने देखा केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण

### ■ यह विकसित भारत का संकल्प पत्र है : अमरजीत छाबड़ा

**रायपुर ।** राजधानी के जोन-7, मंगलम भवन प्रांगण अग्रसेन चौक में जवाहर नगर मंडल के पदाधिकारियों ने नागरिकों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का सीधा प्रसारण देखा और देश की आर्थिक दिशा पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर जवाहर नगर मंडल के मेडिया प्रभारी प्रणीत जैन ने बताया कि आज के बजट लाइव प्रसारण कार्यक्रम पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने

कहा कि यह बजट समावेशी विकास को समर्पित है। इसमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यकों, युवाओं और मध्यम वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जवाहर नगर मंडल के अध्यक्ष संदीप जंघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विचार साझा किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वार्ड पार्षद एवं जोन 7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के लिए किए गए प्रावधानों से स्थानीय स्तर पर भी प्रगति के नए द्वार खुलेंगे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा जी,मंडल अध्यक्ष संदीप जंघेल,तात्यापारा वार्ड पार्षद एवं जोन 7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा जी,पार्षद अवतार सिंग,पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश पांडे जी,महामंत्री रमेश शर्मा,गीता रेड्डी, सूरज शर्मा,शंकर शर्मा, रिखी राम श्रीवास,प्रमोद विश्वकर्मा,मनोज विश्वकर्मा,प्रणीत जैन,कान्हा सिंह ठाकुर,विजय गुप्ता,कुशल गेंडेकर,पीलू कुलदीप,पूनम सोनी,प्रियंका साहू,एकता गुप्ता,नीलू तलमेल,सरोज गुरुगोसाई,के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी, वार्ड के नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने बजट की जनहितकारी योजनाओं का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया।

## फोन टैपिंग मामले में केसीआर से एसआईटी की पूछताछ जारी

**हैदराबाद।** फोन टैपिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से विशेष जांच दल (एसआईटी) की पूछताछ रविवार को हैदराबाद स्थित उनके आवास पर जारी रही।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एसआईटी के अधिकारी दोपहर करीब 3 बजे बंजारा हिल्स के नंदी नगर स्थित केसीआर के घर पहुंचे। अधिकारियों के पास कई दस्तावेज देखे गए, जिन्हें मामले से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केसीआर से आरोपियों के बयानों के आधार पर सवाल किए जा रहे हैं। एसआईटी के अधिकारी केसीआर के घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान उनके पुत्र और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) सहित परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद रहे। पुलिस ने किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए केसीआर के आवास के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया है। नंदी नगर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा केसीआर के समर्थन में जुटने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक बदले की भावना से केसीआर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले, एसआईटी द्वारा दूसरा नोटिस जारी किए जाने के बाद केसीआर सिद्दिपेट जिले के एर्रावली गांव से हैदराबाद पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एसआईटी ने केसीआर को शुक्रवार (30 जनवरी) को पूछताछ के लिए तलब किया था। उन्हें हैदराबाद के भीतर किसी भी स्थान पर उपलब्ध रहने को कहा गया था, लेकिन केसीआर ने नगर निकाय चुनावों में व्यस्तता का हवाला देते हुए किसी अन्य तारीख की मांग की थी। केसीआर ने एर्रावली स्थित अपने आवास पर पूछताछ कराने का अनुरोध भी किया था, जिसे एसआईटी ने खारिज कर दिया। इसके बाद 30 जनवरी की रात हैदराबाद स्थित उनके घर पर नोटिस चस्पा कर उन्हें रविवार को हैदराबाद में ही पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया।

## मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने पीपरछेड़ी में चलाया गया जन-जागरूकता अभियान

### ○ वन विभाग व एनजीओ अर्थ रिट्रीट फाउंडेशन की पहल

**रायपुर ।** वन-जलवायु परिवर्तन विभाग ने अर्थ रिट्रीट फाउंडेशन के साथ गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और ग्रामीणों में सतत जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से ग्राम पीपरछेड़ी में एक विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित

करना रहा। शनिवार को आयोजित यह कार्यक्रम गरियाबंद वनमंडल के परिक्षेत्र पांडुका, उपवन परिक्षेत्र पिपरछेड़ी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को वन्यजीवों से संभावित खतरों, सुरक्षा उपायों, संघर्ष की स्थिति में अपनाए जाने वाले व्यवहारिक तरीकों तथा शासन की मुआवजा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लोककला और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ा जनसरोकार

अभियान को जनसुलभ और प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला, पोस्टर, पेंटिंग और लोकनृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। सरल भाषा और सांस्कृतिक माध्यमों के चलते ग्रामीणों की भागीदारी उल्लेखनीय रही और कार्यक्रम एक जनआंदोलन का रूप लेता नजर आया। एनजीओ अर्थ रिट्रीट फाउंडेशन की अहम भूमिका

इस अभियान में अर्थ रिट्रीट फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एनजीओ की फाउंडर अनुभा उपाध्याय ने ग्रामीणों को खुले कुओं, जल स्त्रोतों और अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों को सुरक्षित करने, वन्यजीव गतिविधियों की तत्काल सूचना वन विभाग को देने तथा किसी दुर्घटना या हमले की स्थिति में उपलब्ध शासकीय मुआवजा प्रावधानों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को फूल से धूप बनाने, दोना-पत्तल निर्माण जैसे वैकल्पिक आजीविका से जुड़े प्रशिक्षण भी प्रदान किए।

**वृक्षारोपण कर लिया संरक्षण का संकल्प**

पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण किया गया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर पौधारोपण कर वन-संरक्षण और सतत विकास का संकल्प लिया।

**'मानव जीवन और वन्यजीव संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता' : शशिगानन्द**

कार्यक्रम में वनमंडल अधिकारी शशिगानन्द मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ जनपद अध्यक्ष मीरा ठाकुर और अर्थ रिट्रीट फाउंडेशन की फाउंडर अनुभा उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।

## रांची के खादगढ़ा बस टर्मिनल में लगी भीषण आग, छह बसें जलकर हुईं खाक

**रांची।** रांची के खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में रविवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बस स्टैंड परिसर में खड़ी कई बसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक कुल छह बसें इसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें आसमान तक उठती दिखीं, जबकि पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड में पहले दो बसों में आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए पास में खड़ी अन्य बसों तक पहुंच गई। आग की चपेट में आई बसों में दो बसें एलडी मोटर्स की बताई जा रही हैं। आरोप है कि कुछ अज्ञात उचक्कों ने जानबूझकर बसों में आग लगाई और मौके से फरार हो गए। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इन बसों में एक भी यात्री नहीं था।

घटना के बाद बस टर्मिनल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। चालक, परिचालक और यात्री इधर-उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोग भी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए और पानी व अन्य उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई।

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, बसों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस स्टैंड व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

इस संबंध में बस मालिकों द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। दो वर्ष पूर्व भी इस बस टर्मिनल में एक साथ चार-पांच बसों में आगजनी की घटना हुई थी।

## सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी को एक साथ गति देगा बजट 2026

**लखनऊ।** केंद्रीय बजट 2026 में सोलर, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी से जुड़ी कस्टम ड्यूटी एवं आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश में लागू प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और राज्य के उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर देखा जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसले प्रदेश में रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी-इन चारों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर

बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रिड-स्तरीय बैटरी स्टोरेज और पावर सिस्टम बैलेंसिंग को मिलेगा। सोलर आधारित बिजली उत्पादन में दिन-रात और मौसम के अनुसार आने वाले उतार-चढ़ाव को बैटरी स्टोरेज के माध्यम से बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। इससे उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी बनने की संभावना है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम और स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमॉनेट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। यह सोलर ग्लास का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो ग्लास की गुणवत्ता, मजबूती और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ड्यूटी हटने से सोलर ग्लास और इसके माध्यम से सोलर मॉड्यूल व पैनल की लागत घटेगी। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मिलेगा, जहां रूफटॉप सोलर सिस्टम सस्ते होने से अधिक घर इस योजना से जुड़ सकेंगे और उपभोक्ताओं को बिजली बिल में उल्लेखनीय राहत मिलेगी।

# तेल के खेल में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता, भारत-वेनेजुएला वार्ता के बाद दुनिया में मची हलचल

भारत और वेनेजुएला के बीच कूटनीति ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस वार्ता का सीधा संबंध तेल से है और इसका परोक्ष असर भारत रूस निर्भरता घटाने, अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है।

सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल आयात में प्रतिदिन कई लाख बैरल की कटौती कर सकता है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ऊर्जा सहयोग पर सहमति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक संदेश में कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा दृष्टि रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। दशकों तक कठोर सरकारी नियंत्रण के बाद अब कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। खोज, उत्पादन, वितरण और विपणन में निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है। कर और रॉयल्टी घटाई गई हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुल्क और कम किए जा सकते हैं और विवादों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खोला गया है। इस तरह यह बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर की राष्ट्रीयकरण नीति को पलट दिया गया है।

अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाते हुए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी है। नया सामान्य लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के निर्यात, भंडारण, परिवहन और परिशोधन की अनुमति देता है, हालांकि भुगतान और कुछ देशों से जुड़े लेन-देन पर सख्त शर्तें रखी गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दिशा बदली है।

देखा जाये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ा है, व्यापार शुल्क भारी हुए हैं और प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति व्यवस्था जटिल हो गई है। इसी वजह से भारत अब तेल आयात के नए विकल्प तलाश रहा है। आयात के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रूस से तेल खरीद दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके साथ ही ओपेक देशों से आने वाले तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली है और आपूर्ति स्रोत बदलने शुरू कर दिए हैं।

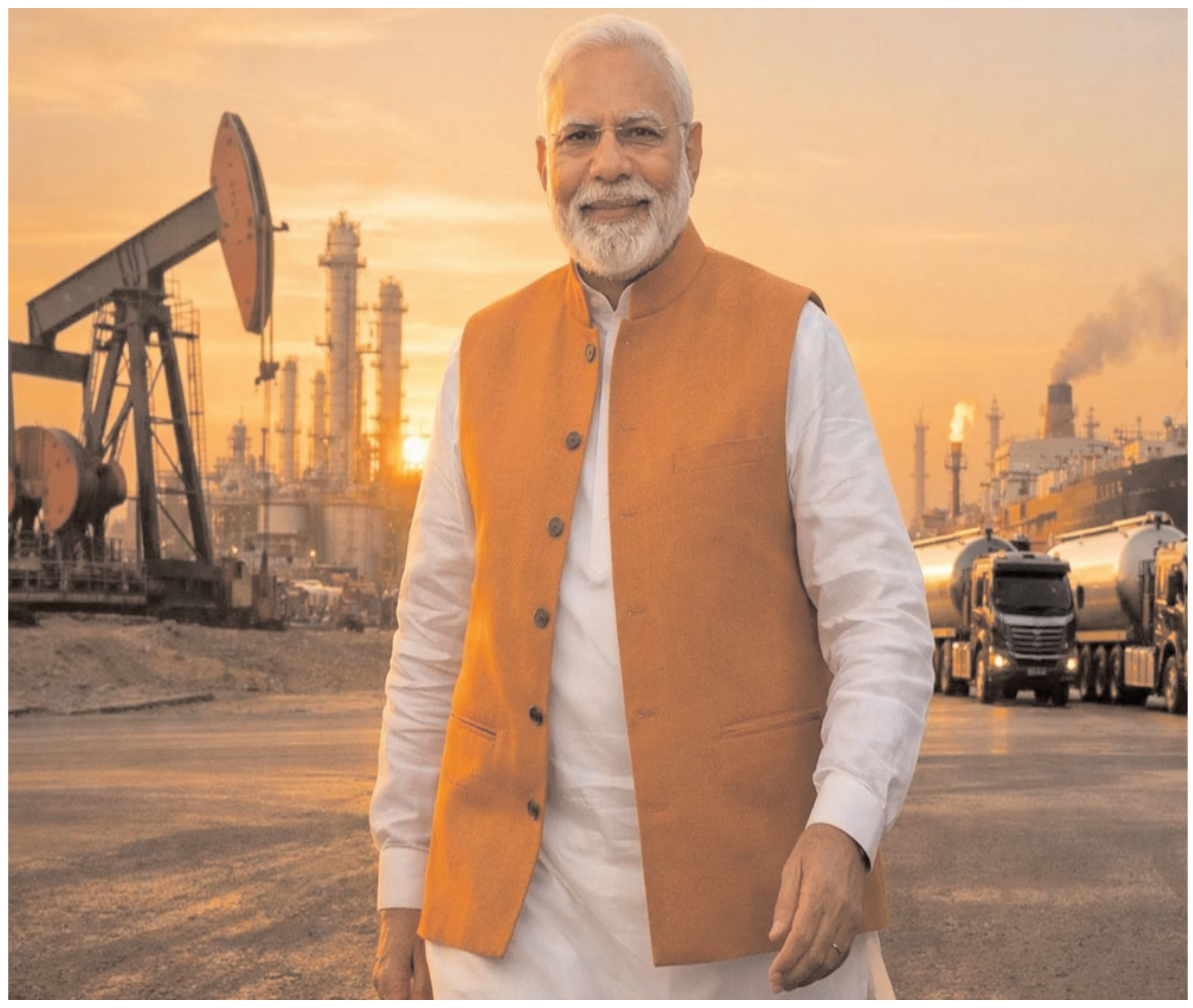

इसी बीच, वेनेजुएला के नए कानून ने एक नई संभावना खोली है। उत्पादन और निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते जो तेल पहले मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह बेहतर कीमत और कम लागत के साथ खुले बाजार में उपलब्ध होगा। सरकारी आकलन के अनुसार, वेनेजुएला में इस साल उत्पादन में 18 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है, जबकि निजी अनुमान इससे भी तेज उछाल की ओर संकेत कर रहे हैं।

देखा जाये तो मोदी और रोड्रिगेज की बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामरिक संकेत है। भारत साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि वह किसी एक स्रोत या किसी एक धड़े के साथ नहीं रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक संप्रभुता की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुध्रुवीय नीति अनिवार्य है। वेनेजुएला के दरवाजे खुलना भारत के लिए अवसर की तरह है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार तक पहुंच सस्ती और स्थिर आपूर्ति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत को अमेरिकी शर्तों, भुगतान नियमों और भू-राजनीति की रस्साकशी में संतुलन भी साधना होगा।

सामरिक रूप से यह कदम रूस पर निर्भरता घटाकर भारत की सौदेबाजी की शक्ति को और बढ़ाता है। यदि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, साथ ही लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ के मंच पर भी यह संकेत जाएगा कि भारत ठोस साझेदारी करता है। वहीं वेनेजुएला ने नियम सरल कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक यथार्थ विचारधारात्मक जिद से बड़ा होता है। निजी निवेश, कम कर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और पारदर्शिता से ही उत्पादन बढ़ेगा और आम नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। भारत यदि यहां निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौते करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा।

बहरहाल, इस पूरी तस्वीर के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी विदेश नीति साफ दिखाई देती है। कच्चे तेल की खरीद और आपूर्ति के मोर्चे पर उन्होंने खुद को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल संकट से जूझ रही थी, तब भारत पर भी हर तरफ से दबाव था कि वह सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए बहुस्तरीय कूटनीति अपनाई।

रूस से तेल खरीद जारी रखी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आपूर्ति संतुलित की और अब लैटिन अमेरिका की ओर रणनीतिक कदम बढ़ा दिये हैं। इसी संतुलित नीति का नतीजा रहा कि जहां यूरोप और अमेरिका में ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं। यह केवल आर्थिक प्रबंधन नहीं था, बल्कि वैश्विक दबावों के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था। देखा जाये तो मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली लगातार कुशल रणनीति के साथ फैसले कर रही है। यही आक्रामक यथार्थवाद आज के दौर की मांग है।

**-नीरज कुमार दुबे**

## करेला के ये फायदे जानते हैं आप? जानें किन परेशानियों में कर सकते हैं सेवन

**नई दिल्ली।** करेला का नाम सुनकर ही मुंह भी कड़वा हो जाता है, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सिर्फ करेला खाने के ही फायदे नहीं हैं, बल्कि इसे लगाने के भी अलग फायदे हैं। करेला रक्त को शुद्ध करने से लेकर विटामिन ए, बी और सी की पूर्ति शरीर में करता है। आयुर्वेद में करेले को 'करवेल्लक' कहा जाता है, जो दूषित रक्त, बढ़ी हुई शर्करा और कीड़ों तक को साफ करने की क्षमता रखता है। करेला अग्नि और अग्न्याशय तक पहुंचने वाली एक शुद्धिकरण औषधि है, जो गहराई से रक्त को पोषण देकर आंतों के कीड़े, घाव को भरने और

त्वचा विकारों की जड़ तक कार्य करता है और शरीर को कई बीमारियों से राहत दिलाने की ताकत रखता है। करेला स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी दवा की तरह काम करता है, क्योंकि यह माताओं में दूध बनाने वाले हार्मोन का उत्पादन तेजी से करता है। हालांकि, इसका सेवन चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें। अगर शरीर पर किसी तरह के घाव हो गए हैं तो करेले का लेप दवा की तरह काम करता है। ये घाव को भरने में मदद करता है, घाव के संक्रमण को रोकता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। आंतों का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आंतों में कई दिनों तक मल साफ नहीं होता है, तो आंतों में कीड़े और बुरे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में भूख कम लगती है, खाना खाते ही शौच जाना पड़ जाता है और खाया-पीया शरीर को लगता नहीं है। ऐसे में करेले को जूस या सलाद के रूप में सेवन किया जा सकता है। करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए नमक लगाकर कुछ घंटों के लिए रख दें, इससे करेला पानी छोड़ देगा और उसका कड़वापन भी कम होगा।

अगर चेहरे पर एक्ने और मुंहासे बहुत होते हैं, तो ये रक्त की अशुद्धि का संकेत हैं। रक्त को शुद्ध करने के लिए रोजाना करेले के जूस का सेवन करना लाभकारी रहेगा। ये रक्त को शुद्ध कर चेहरे पर निखार लाएगा और खुजली और रूखेपन से भी राहत मिलेगी। करेला इन सभी मूल कारणों को संतुलित करता है। यह शरीर को स्वयं ठीक होने की शक्ति को लौटाता है।

## चित्रक: आयुर्वेद की वह जड़ी-बूटी, जो पेट से लेकर जोड़ों तक सब का रखती है ख्याल

**नई दिल्ली।** आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो सदियों से लोगों के स्वास्थ्य का सहारा बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है चित्रक। दिखने में साधारण लेकिन गुणों में बेहद शक्तिशाली यह औषधि खास तौर पर अपनी जड़ के लिए जानी जाती है। पुराने समय में जब आधुनिक दवाइयां नहीं थीं, तब पेट की गड़बड़ी, जोड़ों के दर्द और कई अंदरूनी बीमारियों में चित्रक का इस्तेमाल आम बात थी। आज भी आयुर्वेद में इसका महत्व उतना ही बना हुआ है। सबसे पहले बात करें पाचन की, तो चित्रक को पेट का सच्चा दोस्त कहा जा सकता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस बनती है या बार-बार पेट फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए चित्रक बहुत उपयोगी माना जाता है। यह पाचन अग्नि को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी और ठीक तरह से पचता है। आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन सही होता है, तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। चित्रक की एक और खासियत है इसके कृमिनाशक गुण। पेट में कीड़े होना बच्चों से लेकर बड़ों तक की आम समस्या है। सीमित और सही मात्रा में चित्रक का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने में मदद करता है। यही वजह है कि पुराने वैद्य इसे आंतों से जुड़ी समस्याओं में अहम औषधि मानते थे। अब बात करें जोड़ों और हड्डियों की तो चित्रक यहां भी पीछे नहीं है। यह वात और कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, सूजन, कमर दर्द या शरीर में अकड़न जैसी समस्याओं में चित्रक का उपयोग लाभदायक माना जाता है। कई जगहों पर इसका लेप बनाकर दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है, जिससे आराम मिलता है। खासतौर पर ठंड के मौसम में जब जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तब चित्रक उपयोगी साबित हो सकता है। त्वचा से जुड़ी परेशानियों में भी चित्रक का नाम लिया जाता है। दाद, खुजली, फोड़े-फुंसी या पुराने त्वचा रोगों में इसके जीवाणुनाशक गुण काम आते हैं।

# युवा बजट 2026-27 के आर्थिक मायने विशिष्ट, सियासी प्रभाववश विकसित भारत 2047 के सपने पूरे होंगे

भारत सरकार का 2026-27 का केंद्रीय बजट विकास, रोजगार सृजन और राजकोषीय अनुशासन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026, दिन रविवार को इसे संसद की पटल पर प्रस्तुत करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लिहाजा इसके आर्थिक मायने और राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसपर बहस तेज हो गई, जो कई कारणों से अभिप्रेरित है। जहां सत्ता पक्ष ने इसे युवा शक्ति का प्रतीक बजट ठहराया, वहीं विपक्ष ने इसे अदृश्य बजट करार देते हुए जमकर आलोचना की।

जहां तक कुल बजट आकार की बात है तो यह 53.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। भले ही राजकोषीय घाटा जीडीपी (GDP) का 4.3% रखा गया, जो पिछले साल के 4.4% की तुलना में कुछ कम है। वहीं, जहां तक कर सुधार की बात है तो आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं आया; जबकि नया आयकर अधिनियम 2026 अप्रैल से लागू होगा। वहीं, एफ एंड ओ (F&O) पर एसटीटी (STT) बढ़ाकर 0.05-0.15% किया गया, विदेशी पर्यटन/शिक्षा हेतु टीसीएस (TCS) 2% किया गया।

जहां तक बजट में क्षेत्रीय प्रावधान किये जाने की बात है तो रोजगार-एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का वृद्धि कोष प्रस्तावित है, जबकि क्रेडिट गारंटी दोगुनी की गई। वहीं, बुनियादी ढांचा हेतु 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, शहरी विकास के लिए 5,000 करोड़ प्रति वर्ष का प्रस्ताव और स्वास्थ्य-कृषि क्षेत्र में 17 कैंसर दवाएं सस्ती किये जाने की घोषणा, बायोफार्मा को 10,000 करोड़ दिए जाने का प्रस्ताव और मखाना बोर्ड मजबूत किये जाने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, अन्य महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात प्रोत्साहन पर फोकस प्रदान करते हुए सुधारों का 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' जारी रखा गया। लिहाजा यह विकसित भारत 2047 का रोडमैप है। इन बजट प्रस्तावों के आर्थिक मायने दूरगामी महत्व वाले हैं, क्योंकि बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जो बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा। वहीं, राजकोषीय घाटा 4.3% जीडीपी (GDP) पर लक्षित है, जबकि ऋण-जीडीपी अनुपात 55.6% तक सुधरेगा, जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। वहीं, कर राहत जैसे टीसीएस (TCS)/टैक्स सीमा बढ़ाना, एमएसएमई (MSME) क्रेडिट गारंटी दोगुनी करना और स्टार्टअप फंड कंज्यूमर (consumer) खर्च व निवेश को प्रोत्साहित करेगा। जहां तक बजट प्रस्तावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो निश्चय ही सरकार ने रोजगार (जैसे चमड़ा क्षेत्र में 22 लाख नौकरियां), किसान योजनाएं (मखाना बोर्ड) और स्वास्थ्य (10,000 मेडिकल सीटें) पर फोकस कर एनडीए (NDA) सहयोगियों व ग्रामीण मतदाताओं को मजबूत संदेश दिया है। जबकि विपक्ष ने इसे 'राजनीतिक बजट' करार दिया है, खासकर राज्य-विशिष्ट घोषणाओं पर, लेकिन विकास लक्ष्य (विकसित भारत 2047) बीजेपी की छवि को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर, यह गठबंधन स्थिरता और 2029 के आम चुनाव सहित 2026, 27 और 28 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और अपार अवसर प्रदान करता है। युवाओं के लिए नया आयाम तथा हर घर लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करने वाला बताया। विकास फोकस करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास का माध्यम माना, जो देश को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विपक्ष की आलोचना के बीच सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत करने वाला कदम है।

हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। विभिन्न दलों ने इसे निराशाजनक, फीका और अपेक्षाओं से कम बताया। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इसे 'पूरी तरह फीका' कहा, जिसमें भारी माहौल के बावजूद कोई स्पष्ट आवंटन या पारदर्शिता नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि सरकार अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबो रही है। वहीं कांग्रेस नेता जेबी माथेर ने केरल के लिए इसे निराशाजनक बताया है। वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि के लिए कुछ नहीं है। जबकि सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे गरीब-किसान-युवा विरोधी बजट बताया। जबकि सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि 'मोदी सरकार से ही उन्हें कोई उम्मीद नहीं है।'

वहीं, टीएमसी नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा बजट में भी बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसे 'दिशाहीन' बजट कहा। जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बजट उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए कोई नंबर नहीं देंगे। कुल मिलाकर विपक्ष ने राज्य-विशिष्ट घोषणाओं की कमी, मध्यम वर्ग व किसानों की अनदेखी तथा राजनीतिक बजट करार दिया।

हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष की आलोचना के जवाब में भाजपा सरकार ने इसे ऐतिहासिक, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को सराहते हुए विपक्ष पर तंज कसा कि वे अर्थव्यवस्था की मजबूती को नहीं देख पा रहे। वहीं, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है। जबकि यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे विकसित भारत का रोडमैप करार दिया, और कहा कि इसके विभिन्न प्रस्तावों से सामाजिक-आर्थिक विकास का स्वर्णिम अध्याय पूरा होगा। कुलमिलाकर सरकार ने जोर दिया कि कैपेक्स, रोजगार और किसान योजनाएं विपक्ष की 'फीका' टिप्पणी को गलत साबित करेंगी। इस प्रकार यह बजट एनडीए की एकजुटता को भी दिखाता है।

**- कमलेश पांडेय**
**वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक**

## एसटीटी में बदलाव से लंबी अवधि के निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन : बीएसई सीईओ

**मुंबई ।** सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बदलाव से निवेशक शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही इससे बाजार में लिक्विडिटी में भी बढ़त होगी। यह जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के एमडी और सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति की ओर से रविवार को दी गई। राममूर्ति ने बयान में कहा कि यह केंद्रीय बजट भारत को भविष्य के निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करता है। इससे पूंजीगत बाजार अधिक गहरे एवं ज्यादा संतुलित होंगे और यह देश की लंबी अवधि की आर्थिक प्राथमिकता के अनुरूप है। यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पूंजी निर्माण, राजकोषीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सेवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे प्रमुख विकास स्तंभों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, 'बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च से पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।' मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल ने कहा कि यह बजट भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक मास्टरस्ट्रोक है। उन्होंने एक बयान में कहा, 'पूंजी बाजारों पर एसटीटी के प्रभाव के बारे में हमें यथार्थवादी होना चाहिए। एसटीटी में वृद्धि और डिविडेंड सेट-ऑफ को हटाने से बाजारों में कमजोरी देखी जा रही है। इससे कई हाई-फ्रीक्वेंसी और आर्बिट्रेज ट्रेड अव्यवहार्य हो जाएंगे, जिससे अल्पावधि में बाजार की तरलता और लीवरेज पर दबाव पड़ेगा।' अग्रवाल ने आगे कहा, 'लेकिन विवेकपूर्ण 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ, दीर्घकालिक आय ही भारत के लिए असली हीरो है।' बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरधारकों को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा।

## एसटीटी में बढ़ोतरी से निराश बाजार; सेंसेक्स 1,547 अंक गिरा तो निफ्टी करीब 2 प्रतिशत टूटा

**मुंबई ।** केंद्रीय बजट 2026 के चलते रविवार को विशेष कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,546.84 अंकों यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 पर कारोबार कर रहा था। तो वहीं निफ्टी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 पर था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 79,899.42 के निचले स्तर तक पहुंच गया था और करीब 3,000 अंकों की इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। तो वहीं, निफ्टी50 भी फिसलकर 24,572 तक आ गया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफ एंड ओ) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी करने की घोषणा की और फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया। तो वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.10 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया। इस बड़ी घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। बजट के बाद निवेशक सतर्क नजर आए, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया। हालांकि बजट में आर्थिक विकास को तेज करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की बातें कही गईं, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में भी भारी बिकवाली का दबाव रहा। निफ्टी मिडकैप 100 में 2 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 2.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बाजार की घबराहट को दिखाने वाला इंडिया वीआईएक्स करीब 12 प्रतिशत उछल गया, जो निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। सेक्टोरल स्तर पर आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 6 प्रतिशत टूट गया, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 4 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 2 प्रतिशत से ज्यादा फिसल गए। निफ्टी50 के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को और ओएनजीसी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे और इनमें करीब 5-6 प्रतिशत तक की गिरावट आई। इसके अलावा एसबीआई, अदाणी पोर्ट्स, कोल इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नेस्ले इंडिया, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बड़े गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे।

## बजट 2026 में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने फोकस बढ़ाया, पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 12.2 लाख करोड़ रुपए किया

**नई दिल्ली ।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ाना है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि

आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।

## बजट 2026: छोटे शहरों में रियल एस्टेट को नई रफ्तार, निवेश और विकास की संभावनाएं मजबूत

**नोएडा ।** केंद्रीय बजट 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। इस बार बजट का फोकस केवल बड़े महानगरों तक सीमित न रहकर छोटे और मध्यम आकार के शहरों यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट के संतुलित और टिकाऊ विकास की नींव रख सकता है। बजट की अहम घोषणाओं में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए संपत्तियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत पुरानी या कम उपयोग में आने वाली सरकारी और निजी संपत्तियों को मॉनेटाइज किया जा सकेगा। इससे प्राप्त पूंजी को नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जिससे सेक्टर में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। साथ ही, पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बजट 2026 को मजबूत माना जा रहा है। सरकार ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की योजना का ऐलान किया है। इन परियोजनाओं से प्रमुख शहरों के साथ-साथ उनके आसपास के इलाकों में लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग, औद्योगिक पार्क और नई टाउनशिप विकसित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से छोटे शहर बड़े आर्थिक केंद्रों से जुड़ेंगे, जिससे वहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा, बजट में 12.2 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास को गति देगा। सड़कों, मेट्रो, रेल और शहरी सुविधाओं में सुधार से नए इलाकों में आवासीय परियोजनाएं आकर्षक बनेंगी। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में 20,000 करोड़ के कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स से रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जैसी पहलों से फंडिंग में भरोसा बढ़ेगा और लंबे समय वाले प्रोजेक्ट्स में जोखिम कम होगा। इससे प्रोजेक्ट्स की समय पर डिलीवरी, बेहतर गुणवत्ता और संगठित विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 न केवल निवेशकों का विश्वास मजबूत करता है, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों में रियल एस्टेट को नई पहचान और नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

## कीमती धातुओं के ईटीएफ के प्राइस बैंड में बदलाव सिर्फ आज के लिए: बीएसई

**मुंबई ।** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने रविवार को साफ किया कि सोने और चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए इंट्राडे प्राइस बैंड तय करने में जो रेफरेंस प्राइस बदला गया है, वह सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ही लागू होगा। स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि यह फैसला आज के ही ट्रेडिंग सेशन पर लागू होगा। इससे पहले बीएसई ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर 20 प्रतिशत की सर्किट लिमिट लगाई थी। बीएसई ने अपने बयान में कहा, 'पिछले सर्कुलर के संदर्भ में ट्रेडिंग मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के प्राइस बैंड के लिए रेफरेंस प्राइस में जो बदलाव किया गया है, वह केवल आज के लिए मान्य है।' रेफरेंस प्राइस वह आधार कीमत होती है, जिसके आधार पर दिन के कारोबार में शेयर या ईटीएफ की ऊपरी और निचली सीमा (प्राइस बैंड) तय की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज ने पहले बताया था कि ईटीएफ की कीमत पिछले दिन के नेट एसेट वैल्यू (टी-1 एनएवी) पर आधारित होगी, जिसे संबंधित म्यूचुअल फंड जारी करते हैं। इसी आधार कीमत के ऊपर और नीचे 20 प्रतिशत का प्राइस बैंड लगाया जाएगा। यह कदम कीमती धातुओं के बाजार में आई तेज गिरावट के बाद उठाया गया है। एक्सचेंज का कहना है कि इसका मकसद दिन के अंदर ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकना और निवेशकों को भारी कीमतों के झटके से बचाना है। रविवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। बीते एक साल में तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना करीब 10 बजे 7.12 प्रतिशत गिरकर 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी 9 प्रतिशत गिरकर 2,65,652 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।

चॉइस वेल्थ के हेड ऑफ रिसर्च अक्षत गर्ग ने कहा कि स्क्रीन पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आई तेज गिरावट डरावनी लग सकती है, लेकिन यह ज्यादा भावनाओं का असर है, न कि किसी बड़ी नकारात्मक खबर का। उन्होंने आगे कहा, 'पिछले एक साल में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी से उछाल आया था, और अब हम जो देख रहे हैं वह मुनाफावसूली, वैश्विक अस्थिरता और मैक्रो आर्थिक संकेतों पर प्रतिक्रिया का मिलाजुला असर है। ऐसे दिनों में ईटीएफ की कीमतें ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ने को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं।' उन्होंने निवेशकों को घबराने से बचने की सलाह दी और कहा कि कीमती धातुओं को 'ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए' देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने तेजी के पीछे भागने के बजाय गिरावट के समय धीरे-धीरे निवेश करने की सलाह दी।

## जनवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 28 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी, हुआ 21.70 अरब ट्रांजैक्शन : एनपीसीआई

**नई दिल्ली ।** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए जनवरी में ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में कुल 21.70 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन की कुल राशि में भी 21 प्रतिशत की सालाना बढ़त के साथ यह 28.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रविवार को जारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। एनपीसीआई के मुताबिक, महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता रहा। जनवरी महीने में रोजाना औसतन 91,403 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, जो दिसंबर के 90,217 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। जनवरी में रोजाना औसतन 70 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 69.8 करोड़ था। दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 21.63 अरब रही थी। वहीं ट्रांजैक्शन की राशि 20 प्रतिशत बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सेवा (आईएमपीएस) के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। यह पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा था और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रहा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब 70.9 करोड़ एक्टिव यूपीआई क्यूआर कोड हो चुके हैं, जो जुलाई 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, ट्रांसपोर्ट केंद्रों और ग्रामीण बाजारों में क्यूआर कोड की आसान उपलब्धता ने 'स्कैन और पे' को पूरे देश में आम भुगतान तरीका बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति से दुकानदार को किए जाने वाले (पीटूएम) भुगतान, व्यक्ति से व्यक्ति (पीटूपी) भुगतान की तुलना में ज्यादा रहे। इससे रोजमर्रा की खरीदारी में यूपीआई की मजबूत पकड़ दिखती है। पीटूएम ट्रांजैक्शन 35 प्रतिशत बढ़कर 37.46 अरब तक पहुंच गए, जबकि पीटूपी ट्रांजैक्शन 29 प्रतिशत बढ़कर 21.65 अरब हो गए। औसतन हर ट्रांजैक्शन की राशि घटकर 1,262 रुपए रह गई, जो पहले 1,363 रुपए थी। इससे साफ है कि लोग अब यात्रा, खाना, दवाइयों और छोटे स्थानीय कारोबार में यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) सभी लोगों तक सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे शहर और गांव के बीच की दूरी कम हुई है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश के रूप में उभर रहा है।

## कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, कीमत 49 रुपए बढ़ी

**नई दिल्ली ।** तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 1 फरवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 49 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं। यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लागू होगी, जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों में किया जाता है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत 1,740.50 रुपए हो गई है।

तो वहीं मुंबई में संशोधित कीमत 1,692 रुपए है, जबकि कोलकाता में यह बढ़कर 1,844.50 रुपए हो गई है। वहीं चेन्नई में सिलेंडर की कीमत अब 1,899.50 रुपए होगी।

यह बदलाव तेल कंपनियों द्वारा हर महीने की जाने वाली कीमत समीक्षा के तहत किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और देश के अंदर की लागत पर आधारित होती है। इस कीमत बढ़ोतरी का असर खाने-पीने और होटल से जुड़े कारोबार पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी एक जरूरी ईंधन है।

हाल के महीनों में व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी में, ओएमसी ने कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि पिछले साल नवंबर में 5 रुपए और दिसंबर में 10 रुपए की कमी की गई थी।

दिल्ली में, पिछले साल मार्च में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1,803 रुपए थी, जिसके बाद 2024 और 2025 की शुरुआत में कई बार कटौती और बढ़ोतरी हुई। दिसंबर में गिरकर 1,580.50 रुपए होने के बाद, कीमतों में अब लगातार दो महीनों से वृद्धि हो रही है।

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, ओएमसी ने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी की कीमतें अपरिवर्तित हैं, और आखिरी संशोधन 8 अप्रैल, 2025 को हुआ था।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा हर महीने की शुरुआत में की जाती है। कीमतों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों, मुद्रा विनिमय दर और परिवहन लागत जैसे कारणों पर निर्भर करता है।

इस तरह, जहां कारोबारियों पर गैस महंगी होने का असर पड़ेगा, वहीं आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है।

## एफएंडओ में तेजी से बढ़ रही सट्टेबाजी को कम करने के लिए एसटीटी में की बढ़ोतरी: केंद्र

**नई दिल्ली ।** केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में तेजी से बढ़ रही सट्टेबाजी और प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ाने का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी के साथ-साथ एसटीटी से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है। बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरधारकों को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स पर कहा कि नए संरचना के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर प्रभावी रूप से 22 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक लेनदेन के लिए 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। एसटीटी में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,546.84 अंक या 1.88 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,722.94 और निफ्टी 495.20 अंक या 1.96 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,825.45 पर बंद हुआ। इस ऐलान के कारण निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स 5.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं, ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म एंजेल वन और ग्रो के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली। एंजेल वन लिमिटेड के ग्रुप चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर अमित मजूमदार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में, एफएंडओ ब्रोकरेज ने हमारे कुल राजस्व में लगभग 44 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि क्लाइंट फंडिंग और हमारे व्यापक प्लेटफॉर्म से प्राप्त ब्याज आय लगभग 33 प्रतिशत रही, शेष आय कैश और कमोडिटी ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य आय स्रोतों से आई। एसटीटी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए प्रतिभूति लेनदेन के मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है। यह इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में किए गए ट्रेड्स पर लागू होता है। यह कर लेनदेन के समय ही वसूला जाता है, चाहे निवेशक को लाभ हो या हानि। विशेषज्ञों ने इंट्रा-डे स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण एसटीटी शुल्क में वृद्धि को बताया। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के आकाश शाह ने कहा, 'यह मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है और इससे एफएंडओ वॉल्यूम विशेष रूप से हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरी डेस्क और लागत-संवेदनशील रणनीतियों पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

## बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में बड़ी राहत

**नई दिल्ली ।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने के लिए कई सेक्टरों में कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। इनमें समुद्री उत्पाद, कपड़ा, चमड़ा, रक्षा और विमानन जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने सी-फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ इनपुट्स के ड्यूटी-फ्री आयात की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसे पिछले साल के निर्यात टर्नओवर के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि अभी तक चमड़े या सिंथेटिक जूतों के निर्यात के लिए जो ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा मिलती थी, उसे अब जूतों के ऊपरी हिस्से (शू अपर) के निर्यात तक भी बढ़ाया जाएगा। इससे मजदूरों पर आधारित इन उद्योगों में रोजगार और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।

चमड़ा, कपड़ा, सिंथेटिक जूते और अन्य

चमड़ा उत्पादों के निर्यातकों को अब अंतिम उत्पाद भेजने के लिए 6 महीने की जगह 1 साल का समय दिया जाएगा।

लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी पर मिलने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनट के आयात पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

बजट में नागरिक प्रशिक्षण विमानों और अन्य विमानों के निर्माण में लगने वाले पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रावधान किया गया है। रक्षा क्षेत्र यूनिट्स द्वारा विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी।

माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पुर्जों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।

वैश्विक व्यापार में रुकावटों के कारण स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) की कई फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बार की राहत के तहत योग्य एसईजेड यूनिट्स को कम कस्टम ड्यूटी पर घरेलू बाजार में सामान बेचने की अनुमति देने का ऐलान किया है।

न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले सामानों के आयात पर कस्टम ड्यूटी से छूट को 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही यह सुविधा अब सभी परमाणु संयंत्रों को मिलेगी, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो।

देश में जरूरी खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की प्रोसेसिंग के लिए आयात की जाने वाली मशीनों पर भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि बायोगैस से मिले मूल्य को बायोगैस मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर लगने वाली केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

# ब्राउन राइस या व्हाइट राइसः कौन सा चावल है आपकी सेहत के लिए बेहतर?

**नई दिल्ली ।** भारत में लोगों की थाली में चावल का होना आम बात है, क्योंकि यह सालों से यहां के लोगों की डाइट का अहम हिस्सा है। कई राज्यों में लोग दिन की शुरुआत और समापन दोनों समय चावल या चावल से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं।

आमतौर पर लोग सफेद चावल (व्हाइट राइस) या भूरे चावल (ब्राउन राइस) खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उनकी सेहत के लिए कौन सा चावल बेहतर रहेगा। असल में, सफेद चावल (व्हाइट राइस) और भूरे चावल (ब्राउन राइस) में फर्क प्रोसेसिंग का है। ब्राउन राइस अनपॉलिश्ड चावल होते हैं, यानी इनके ऊपर की परतें हटाई नहीं जाती।

इसके कारण इनमें ज्यादा पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। वहीं, व्हाइट राइस पॉलिश्ड होता है और इसकी बाहरी परतें हटा दी जाती हैं।

इससे यह सफेद और नरम बन जाता है, लेकिन पोषण की बड़ी मात्रा खत्म हो जाती है।

ब्राउन राइस में फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और वजन घटाने में मदद करता है। साथ ही, ब्राउन राइस ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर आप शुगर कंट्रोल या वजन कम करना चाहते हैं, तो ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल करना बेहतर हो सकता है।

व्हाइट राइस जल्दी पच जाता है और हल्का स्वाद देता है, इसलिए जिन लोगों की पाचन क्षमता कमजोर है या जिन्हें जल्दी एनर्जी चाहिए, उनके लिए यह ठीक रहता है। लेकिन ध्यान रहे, यह ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा सकता है और पोषण की मात्रा ब्राउन राइस की तुलना में कम होती है।

हालांकि, हर चीज की तरह ब्राउन राइस भी सबके लिए सही नहीं है। इसमें फाइटेट्स होते हैं, जो कुछ मिनरल्स के अवशोषण को रोक सकते हैं। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें इसकी फाइबर की मात्रा परेशान कर सकती है।

## आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अयास का तरीका

**नई दिल्ली ।** आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर्स समेत अन्य गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता आंखों की सेहत के लिए खतरनाक है। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे ड्राई आईज, सिरदर्द, धुंधला दिखना और आंखों में जलन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में कुछ अभ्यास से आंखों को सेहतमंद रखा जा सकता है। बढ़ती आंखों की थकान और कमजोरी को दूर करने में यह कारगर है। आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इनकी देखभाल न करने से भविष्य में गंभीर समस्याएं जैसे कमजोर दृष्टि या अन्य नेत्र रोग हो सकते हैं। नियमित रूप से ये सरल एक्सरसाइज अपनाने से आंखों की रोशनी मजबूत रहती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, आंखों की सेहत के लिए मंत्रालय ने रोजाना हल्की एक्सरसाइज और सरल नियमों का पालन करने की सलाह दी है। आयुष मंत्रालय ने सबसे प्रभावी नियम के रूप में 20-20-20 नियम को अपनाने पर जोर दिया है। इस नियम के अनुसार, हर 20 मिनट में काम से ब्रेक लें, अपनी नजर को स्क्रीन से हटाकर 20 फीट (लगभग 6 मीटर) की दूरी पर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें। यह छोटा-सा अभ्यास आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है, फोकस बदलने से आंखों पर तनाव कम होता है और आंखों की थकान दूर होती है।एक्सपर्ट का कहना है कि यह नियम स्क्रीन पर काम करने वाले छात्रों, ऑफिस कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने आंखों की देखभाल के लिए कुछ अन्य सरल उपाय भी सुझाए हैं। इनमें रोजाना सुबह-शाम 2-3 मिनट पॉमिंग करें, इसके लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और बंद आंखों पर रखें। इससे आंखों को गहरा आराम मिलता है।त्राटक करें, जैसे मोमबत्ती की लौ या काले बिंदु पर बिना पलक झपकाए कुछ सेकंड तक देखें, फिर आंखें बंद कर लें। आंखों की हल्की मालिश करें। आंखों को ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं, गोल-गोल घुमाना और पास-दूर फोकस बदलना भी करें। सबसे महत्वपूर्ण है स्क्रीन टाइम कम करना, अच्छी रोशनी में पढ़ाई या काम करें और पर्याप्त नींद लें।

## डीप फ्राइंग के लिए कौन सा तेल बेहतर? जानें पांच जरूरी नियम

**नई दिल्ली ।** डीप फ्राई खाना आज की जीवनशैली का जरूरी हिस्सा बन गया है। बच्चों से लेकर बड़े तक तले-भुने खाने के शौकीन हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि तले-भुने भोजन में इस्तेमाल होने वाला तेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है।

जब तेल बार-बार तेज आंच पर गर्म होता है तो तेल में ऑक्सीडेशन का स्तर बढ़ जाता है और फ्री रेडिकल्स और ट्रांस-फैट भी बढ़ जाते हैं, जो पेट और आंतों के लिए खतरा है।आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा तेल पाचन अग्नि को मंद करता है और शरीर में 'आम' पैदा करता है, जो शरीर में वसा को बढ़ाकर कई बीमारियों को जन्म देता है। ज्यादा तेल का सेवन या डीप फ्राई चीजों के सेवन से हृदय संबंधी रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सा तेल खाने और डीप फ्राइंग के लिए सही होता है। आयुर्वेद में देसी घी, नारियल के तेल, सरसों का तेल और मूंगफली के तेल को डीप फ्राइंग और खाने में उपयोगी माना गया है। ये सभी तेल उच्च ताप मानक पर भी अपने गुण बनाए रखते हैं। जैसे देसी घी को 250 सेल्सियस पर गर्म करने पर ऑक्सीडेशन का स्तर कम बना रहता है और फ्री रेडिकल्स भी कम बनते हैं। नारियल के तेल में लगभग 90 प्रतिशत सैचुरेटेड फैट होता है, जो बार-बार गर्म करने पर भी बाकी तेलों की तुलना में ऑक्सीडेशन कम बनाता है। वैसे ही मूंगफली के तेल का उच्च ताप मानक 230 सेल्सियस होता है और ज्यादा गर्म होने पर भी फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं। हालांकि इसे बार-बार गर्म करना सेहत के लिए हानिकारक है।

अब जानते हैं कि किन तेलों के उपयोग से बचना चाहिए। डीप फ्राई के लिए सोयाबीन, सूरजमुखी, कॉर्न ऑयल, राइस ब्राउन, और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आयुर्वेद में डीप फ्राइंग के पांच नियमों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है, तेल को बार-बार प्रयोग करने से बचना, धुआं उठने के बाद तेल का इस्तेमाल न करना, अलग-अलग तेलों को मिलाने से बचना, तलने के बाद छानकर ही पुनः प्रयोग में लाना, और मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल करना शामिल है।

## योग की ताकतः ओपिओइड विड्रॉल रिकवरी 4 गुना तेज, तनाव होता है दूर

**नई दिल्ली।** एक नई स्टडी के मुताबिक, योग ओपिओइड विड्रॉल के लक्षणों से तेजी से उबरने में मदद कर सकता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता बढ़ती है और दर्द से राहत भी मिलती है। जामा साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित इस रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहांस), बेंगलुरु और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने 59 पुरुष प्रतिभागियों पर अध्ययन किया, जो ओपिओइड यूज डिसऑर्डर से पीड़ित थे। योग ग्रुप में शामिल लोगों को स्टैंडर्ड बुप्रेनॉर्फिन ट्रीटमेंट के साथ 45 मिनट की योग सेशन दी गई, जबकि कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ दवा दी गई। नतीजे दिखाते हैं कि योग ग्रुप ने विड्रॉल से रिकवरी 4.4 गुना तेजी से की (मीडियन 5 दिन बनाम 9 दिन)। निमहांस के इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की सुड्डाला गौतम ने कहा, 'इस ट्रायल में, योग ने ओपिओइड विड्रॉल रिकवरी को काफी बेहतर बनाया।' ओपिओइड यूज डिसऑर्डर (ओयूडी), जिसकी पहचान बार-बार ओपिओइड के इस्तेमाल से होती है, से गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं होती हैं। ये एक बड़ी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चुनौती है। ओपिओइड छोड़ने पर कुछ दिक्कतें आती हैं। दस्त, नींद न आना, बुखार, दर्द, चिंता और डिप्रेशन जैसे शारीरिक लक्षण उभर आते हैं, और ऑटोनोमिक लक्षण जैसे पुतली का फैलना, नाक बहना, रोंगटे खड़े होना, भूख न लगना, जम्हाई आना, जी मिचलाना, उल्टी और पसीना आने लगता है। योग ने हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (एचआरवी) में सुधार किया, घबराहट को काफी कम किया, नींद आने में लगने वाला समय 61 मिनट घटाया, और दर्द में राहत दी। शोधकर्ताओं का मानना है कि योग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, जो विड्रॉल के लक्षणों को कम करने में 23 फीसदी योगदान देता है।2022 में, दुनिया भर में लगभग 60 मिलियन लोगों ने बिना डॉक्टरी इलाज के ओपिओइड का इस्तेमाल किया। भारत में, 2019 के एक नेशनल सर्वे से पता चला कि ओपिओइड का इस्तेमाल 2.1 प्रतिशत आम बात है। यह स्टडी ओपिओइड संकट से जूझ रहे देशों के लिए एक सस्ता और आसानी से सुलभ विकल्प पेश करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि योग को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करने से रिलैप्स रेट कम हो सकतो है।

## चिंता, डर और बेचैनी को दूर करती है कमल मुद्रा, बढ़ाती है सकारात्मक सोच

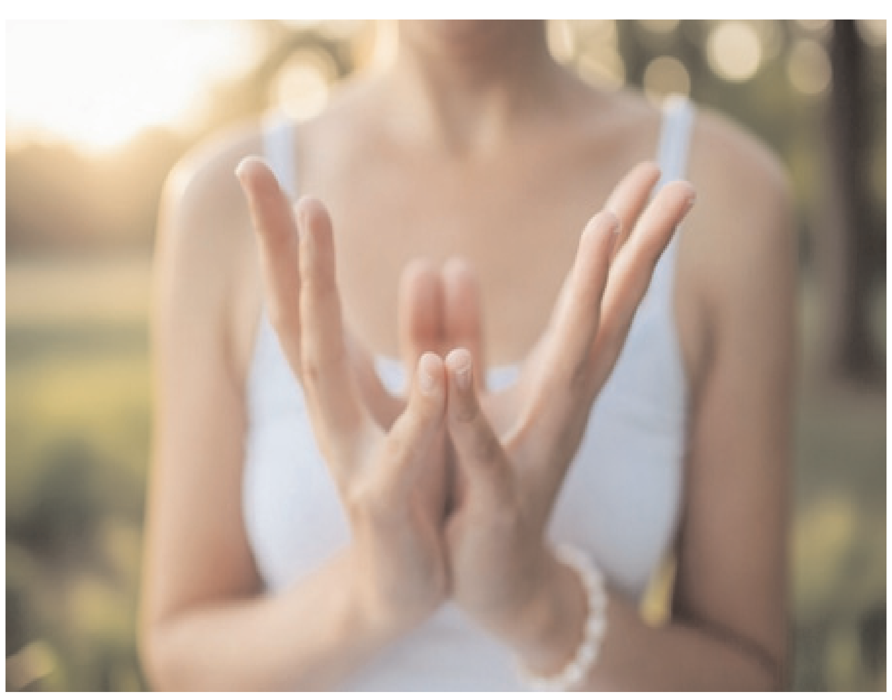

**नई दिल्ली ।** आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका हुआ नजर आता है। ऐसे में योग जीवन को संतुलन बनाने में मदद करता है। योग में कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, जिनका प्रभाव बेहद गहरा होता है। इन्हीं में से एक है सुखासन में पद्म मुद्रा, जिसे कमल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रा शरीर को स्थिरता देती है। पद्म मुद्रा का नाम संस्कृत शब्द 'पद्म' से लिया गया है, जिसका अर्थ है कमल। जब इस मुद्रा को सुखासन में बैठकर किया जाता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है और ध्यान भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। सुखासन में पद्म मुद्रा करने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। यह मुद्रा सीधे तौर पर हृदय चक्र से जुड़ी मानी जाती है। जो भावनात्मक दबाव, डर या नकारात्मक सोच जैसी समस्या से जूझ रहा हो, उनके लिए यह मुद्रा बेहद लाभकारी मानी जाती है। नियमित अभ्यास से भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है और मन हल्का महसूस करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी सुखासन पद्म मुद्रा को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यह मुद्रा गहरी और शांत श्वास को प्रोत्साहित करती है, जिससे नर्वस सिस्टम शांत होता है। तनाव और चिंता की स्थिति में यह मुद्रा मन को स्थिर करने में मदद करती है। यह अभ्यास धीरे-धीरे अवसाद और बेचैनी जैसी समस्याओं को कम करता है। पद्म मुद्रा करते समय शरीर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर सक्रिय होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। जिन लोगों को एसिडिटी, अपच या पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें नियमित अभ्यास से राहत मिल सकती है। इसके अलावा, यह मुद्रा शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह संतुलित करती है, जिससे थकान कम होती है और ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहता है। पद्म मुद्रा के नियमित अभ्यास से न केवल मन शांत होता है, बल्कि सोच धीरे-धीरे सकारात्मक और जीवन संतुलित होने लगता है।

## पाद-स्नानः तन और मन को डिटॉक्स करने का सरल तरीका, कम होगी मानसिक थकान

**नई दिल्ली ।** दिन भर काम की थकान शरीर और मन दोनों को बोझिल कर देती है। लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है।

ऐसा इसलिए क्योंकि दिनभर की थकान सिर्फ़ शरीर में नहीं ठहरती, वह मन को भी प्रभावित करती है। समझ नहीं आता कि क्या करना है, दवा लेनी भी है या नहीं, मन विचलित होता है। ऐसा होना मन और तन की थकान को दिखाता है, जिसका इलाज आर्युवेद के एक नुस्खे में छिपा है। आयुर्वेद में पाद-स्नान यानी पैरों को गुनगुने नमक जल में रखने की प्रक्रिया मन और तन को शांत करने में मदद करती है।आयुर्वेद में पाद-स्नान (पैरों को गुनगुने नमक जल में रखना) एक सरल संध्या-अभ्यास माना गया है, जो शरीर के भारीपन को कम करता है और मन को विश्राम की दिशा देता है। इससे शरीर और मन के तनाव में कमी होती है और पूरा शरीर रिलैक्स महसूस करता है। इसके लिए सेंधा या समुद्री नमक मिले गुनगुने जल में 10-15 मिनट शांत बैठकर केवल श्वास पर ध्यान रखें। यह एक सौम्य 'बॉडी डिटॉक्स' अभ्यास है, जो नाड़ी-तंत्र को स्थिरता का संकेत देता है। पाद-स्नान करने से शरीर हल्का होता है और मन खुद-ब-खुद शांत होने लगता है। शरीर में होने वाले हल्के दर्द और थकान से भी राहत मिलती है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। पाद-स्नान के बाद शरीर का बोझिल होना कम होता है और मन को भी आराम की अनुभूति होती है। पाद-स्नान में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है बल्कि ये शरीर के भारीपन को कम करने और शरीर को संतुलित करने में मदद करता है। नमक मन की बैचेनी को संतुलित करने में मदद करता है, जो पानी के साथ मिलकर नाड़ियों के तंत्रिका-तंत्र को शांत करता है। आयुर्वेद में पाद स्नान को चमत्कार की तरह माना गया है। अगर रोजाना शाम के वक्त कमजोरी और मन भारी महसूस होता है, तो ये क्रिया शरीर को संतुलित करने में मदद करेगी। इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना सही रहेगा। पाद-स्नान मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है। आज का काम शरीर के साथ-साथ मन की थकावट का बड़ा कारण है। पाद स्नान की मदद से तनाव को कम कर मस्तिष्क को आराम दिया जा सकता है। ये शरीर में हैप्पी हॉर्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है।

## क्या हर 27 दिन में पूरी नई हो जाती है आपकी स्किन? आयुर्वेद से जानिए त्वचा से जुड़े गहरे राज

**नई दिल्ली ।** बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी स्किन बदलती रहती है। आज आप आईने में खुद को जैसा देखते हैं, वैसे न तो आप पहले दिखते थे और न ही भविष्य में दिखेंगे। उम्र के साथ हमारी त्वचा भी बदलती रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर 27 से 30 दिन में आपकी त्वचा अपने आप पूरी तरह से नई हो जाती है?

आयुर्वेद की मानें तो हमारी त्वचा इतनी चतुराई से काम करती है कि हर 27 से 30 दिन में लगभग पूरी तरह नई हो जाती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एपिडर्मल टर्नओवर साइकिल कहते हैं। इसका मतलब है कि जो आप आज अपनी त्वचा में देख रहे हैं, वह कल बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी। आयुर्वेद में भी त्वचा को बहुत महत्व दिया गया है। इसे केवल सुंदरता की चीज नहीं माना गया, बल्कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ढाल है। सूरज की हानिकारक किरणें, धूल, बैक्टीरिया और रसायन ये सब हमारी त्वचा से टकराकर शरीर तक नहीं पहुंच पाते। इसमें मौजूद मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं मेलेनिन बनाती हैं, जो सूरज की किरणों से बचाव करती हैं।आपकी त्वचा सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, यह आपकी सेहत की भी सुरक्षा करती है।

स्वेद ग्रंथियां हर दिन 1 से 2 लीटर तक पसीना निकालती हैं। यह शरीर को ठंडा रखती है और साथ ही अंदर से सफाई भी करती है, इसलिए योग, व्यायाम जैसी आदतें न सिर्फ शरीर बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी हैं। रात का समय त्वचा के लिए बहुत खास होता है। दिनभर की धूल, तनाव और सूरज की किरणों के बाद रात में आपकी त्वचा खुद को फिर से बनाती है। नए कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण होता है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी स्किन के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। आहार का भी बहुत असर पड़ता है। विटामिन ए, सी, ई और जिंक से भरपूर चीजें जैसी आंवला, गाजर, पपीता, बादाम और तुलसी त्वचा को अंदर से पोषण देती हैं।

इस वजह से आयुर्वेद में इन्हें त्वच्य औषधि कहा गया है। तनाव, धूम्रपान और नींद की कमी आपकी त्वचा की सेल मेमोरी पर असर डाल सकती है। इसका मतलब है कि आपकी त्वचा ये सब याद रखती है और बाद में झुर्रियों, सूखापन या दाग के रूप में दिखा सकती है।

# ऐश्वर्या राय ने दिखाया अपना सिंगिंग टैलेंट, चंद्रचूड़ सिंह संग गाया 'मेरी सांसों में बसा है' गाना

**मुंबई।** बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा से ही अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन एक पुराने चैट शो में उन्होंने अपनी छुपी हुई प्रतिभा का खुलासा किया।

इस बार फैंस ने सिर्फ उनकी अदाकारी ही नहीं, बल्कि उनकी मधुर आवाज की तारीफ भी की। चैट शो 'जीना इसी का नाम है' के एक एपिसोड में वह अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के साथ पहुंची।

इस दौरान होस्ट फारूक शेख के साथ हल्की-फुल्की मस्ती की। एपिसोड में जब होस्ट ने चंद्रचूड़ सिंह से फिल्म 'जोश' की शूटिंग के दौरान कोई मजेदार या खास किस्सा साझा करने के लिए कहा, तो उन्होंने एक रहस्य का खुलासा किया। चंद्रचूड़ ने बताया कि ऐश्वर्या राय गायन में भी बेहद अच्छी हैं, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, 'ऐश्वर्या जितनी सुंदर दिखतीं हैं, उससे भी सुंदर उनकी गायन शैली है। उनकी आवाज बेहद मधुर है।' चंद्रचूड़ के इस खुलासे के बाद वहां मौजूद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और सभी ने उनसे कुछ गाने की सिफारिश की। इस पर ऐश्वर्या ने हंसते हुए कहा कि असल में गाना तो चंद्रचूड़ ही अच्छे से गाते हैं। इसके बाद होस्ट ने दोनों से आग्रह किया कि वे लोगों की डिमांड पर कुछ गाकर दिखाएं, तो ऐश्वर्या ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'और प्यार हो गया' का गाना 'मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम' को बेहद खूबसूरती के साथ गाया। ऐश्वर्या की आवाज ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें उनका साथ चंद्रचूड़ सिंह ने भी दिया।

एपिसोड के दौरान फारूक शेख ने चंद्रचूड़ सिंह से ऐश्वर्या के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बेहद दयालु और सपोर्टिव हैं।

`उनके साथ काम करना मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य था और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि समझदार और सुलझी हुई इंसान हैं।''

बता दें कि फिल्म 'जोश' 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन मंसूर खान ने किया था। इसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भाई-बहन के किरदार में थे, जबकि ऐश्वर्या और चंद्रचूड़ रोमांटिक जोड़ी में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ शरद कपूर और प्रिया गिल भी मुख्य भूमिकाओं में थे।

# दिल्ली में खुला अनुपम खेर का नया एक्टिंग स्कूल, कहा, राजधानी अब साहस और कला का घर बन गई

**मुंबई।** हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर सिनेमा में वर्सटाइल एक्टिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन साथ ही पर्दे पर कुछ बड़े स्टार्स की प्रतिभा को निखार कर उन्हें करियर बनाने में मदद की। अभिनेता बीते 21 साल से मुंबई में अपना एक्टिंग स्कूल एक्टर्स प्रीपेयर्स चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के कलाकारों को सपनों की उड़ान देने के लिए नया एक्टिंग स्कूल दिल्ली में खोला है। अनुपम खेर ने दिल्ली के कलाकारों को अपने सपने बिना भय के जीने का नया मौका दिया है और 31 जनवरी को दिल्ली में नए एक्टिंग स्कूल का उद्घाटन किया है। अभिनेता नए एक्टिंग स्कूल की ओपनिंग से बहुत खुश हैं क्योंकि अब एक्टिंग में अपना करियर बनाने वाले युवाओं को मुंबई का रुख नहीं करना पड़ेगा। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर कहा, 'राजधानी अब साहस और कला का घर बन गई है। एक ऐसी जगह जहां प्रतिभा को निखारा जाता है, कमजोरी ताकत बन जाती है, और सपनों को ईमानदारी और अनुशासन के साथ संवारा जाता है। अगर आपके मन में कहीं 'क्या हो अगर?' की आवाज़ गूंजती है, अगर एक्टिंग आपका वो सपना है जिसे आपने अब तक के लिए टाल रखा था, तो ये रहा आपका पल।' अभिनेता ने ये भी साफ किया कि उनके मुंबई के एक्टिंग स्कूल एक्टर्स प्रीपेयर्स ने दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टारों को निखारा है। उन्होंने कहा, 'हमने दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टारों को आशा, भय और अटूट सपने से भरे हुए हमारी कक्षाओं में आते देखा है, और फिर वे ऐसे अभिनेता बनकर निकले जिन्होंने विश्वास करने का साहस दिखाया और अपने अनूठे तरीके से सफलता की कहानियां गढ़ीं।' अब मुंबई की तरह दिल्ली में भी कलाकारों की कला को निखारने के लिए अभिनेता ने सिनेमा के आने वाले कल की नींव रख दी है। अब दिल्ली में कला सांस लेगी और उन्हें अपने सपनों को 'काश' कहकर पछतावे की आग में नहीं जलाना पड़ेगा। 31 जनवरी को अनुपम खेर ने 'खोसला का घोसला-2' के अपने कोस्टार बोमन ईरानी के साथ मिलकर एक्टिंग स्कूल का उद्घाटन किया और दिल्ली से कलाकारों से जुड़ने की अपील की।

# अनोखे ट्विस्ट के साथ आज से देखें 'द 50', इस शो से लिया फॉर्मेट का आइडिया

**मुंबई।** रियलिटी शो की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। अब ऐसा ही एक नया शो दर्शकों के लिए रविवार यानी 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसका नाम है 'द 50'। इसमें रोमांच, रणनीति, दोस्ती और सरप्राइज का तड़का है। इसमें कोई तय नियम या फिक्स्ड एलिमिनेशन सिस्टम नहीं है। यहां दर्शकों को सब कुछ अचानक होता दिखेगा। यह शो भारत में बड़े सेलिब्रिटी और रियलिटी स्टार्स के लिए तैयार किया गया है, जहां 50 कंटेस्टेंट्स अपनी समझ, खेल और सर्वाइवल स्किल के दम पर एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे। शो का आइडिया फ्रांस के इंटरनेशनल शो 'लेस सिनक्वांटे' से लिया गया है। फ्रांस में इसका चौथा सीजन युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहा। इसके बाद पोलैंड और जर्मनी में भी यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर लॉन्च हुआ और टॉप रैंक में आया। अमेरिका में हिस्पैनिक चैनल टेलीमुंडो ने इसे प्रसारित किया। अब इस फॉर्मेट को भारतीय दर्शकों की पसंद और जरूरत के अनुसार ढाला गया है। 'द 50' की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा फॉर्मेट है। यहां 50 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को दस टीमों में बांटा गया है, हर टीम में पांच मेंबर हैं और हर टीम का एक कप्तान है। टीमें नियमित टास्क में हिस्सा लेती हैं और इन टास्क में जीतने वाली टीम को पावर और फायदे मिलते हैं, जबकि हारने वाली टीम अनसेफ जोन में चली जाती है। यहां बड़ा ट्विस्ट यह है कि अनसेफ टीम में से बाहर कौन जाएगा, यह जीतने वाली टीमें तय करती हैं। इससे खेल में हमेशा दबाव, योजना और रणनीति बनी रहती है।

हर एपिसोड में नया मोड़ देखने को मिलेगा। कभी कोई शॉकिंग ट्विस्ट आएगा, तो कभी टीम के रिश्ते की बागडोर टूटती दिखेगी। शो में खिलाड़ियों को लगातार सोच-समझकर अपने फैसले बदलने पड़ेंगे।

शो मुंबई के मड आइलैंड में बने बड़े पैलेस स्टाइल सेट पर शूट किया जा रहा है। सेट में एक खास कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिसे 'लॉयन' कहा गया है। यह कंटेस्टेंट्स पर नजर रखता है और गेम की दिशा तय करता है। शो के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में काफी चर्चित हस्तियां शामिल हैं। इसमें करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, उर्वशी ढोलकिया, सपना चौधरी, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, अर्चना गौतम, रजत दलाल और कई अन्य बड़े नाम शामिल हैं। सभी अपने अनुभव और फैन फॉलोइंग के दम पर गेम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे।

शो की मेजबानी फराह खान करेंगी। शो का प्रसारण रवि कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे होगा।

# बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां

**मुंबई।** `बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर दहशत का माहौल है। मुंबई में मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई। इस घटना ने आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सितारे कितने सुरक्षित हैं। रोहित शेट्टी से पहले भी कई बड़े नाम ऐसे हैं, जिनके घर या ऑफिस को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं में कुछ मामलों ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिद्धू मूसेवाला- पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री, बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया।

कपिल शर्मा- कमीडियन कपिल शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर अलग-अलग दिन तीन बार फायरिंग हुई। इन घटनाओं ने कपिल और उनके फैंस के दिलों में डर बिठा दिया था। बताया गया कि इन हमलों की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों ने ली थी।

सलमान खान- सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग की घटना भी काफी चर्चा में रही। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। उस वक्त सलमान खान घर में ही मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसके बाद उनकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। इस मामले में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था।

एपी ढिल्लों- पंजाबी गायक एपी ढिल्लों भी इससे अछूते नहीं रहे। सितंबर 2024 में कनाडा स्थित उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में कनाडा पुलिस ने जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसने फैंस को चिंता में डाल दिया।

# 'आप मेरी ताकत हैं,' मां की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं जया प्रदा

**मुंबई।** 70 और 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल जया प्रदा भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया के जरिए देश की हर घटना पर अपनी राय रखती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी मां नीलावनी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जया प्रदा ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वे अपनी मां पर ढेर सारा प्यार लुटाती दिख रही हैं। जया ने अपनी मां को अपनी हिम्मत बताया, जिन्होंने इस दुनिया में उन्हें जीना सिखाया। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी प्यारी मां की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। आपको इस दुनिया से गए समय बीत गया, लेकिन आपकी यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। आपकी ममता, आपका आशीर्वाद और आपकी सीख हर कदम पर मेरा साथ देती है। आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। आपने जो संस्कार, प्यार और हौसला दिया, वही आज मेरी ताकत है। आप भले आंखों से दूर हों, पर दिल में हमेशा जिंदा हैं।' अभिनेत्री की मां का निधन साल 2022 में हुआ था। वे काफी समय से उम्र संबंधी कई परेशानियों से जूझ रही थीं और काफी बीमार थीं। उनका इलाज हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल से चल रहा था। जया फिल्मों में अपनी एंट्री और सफलता का श्रेय अपनी मां को ही देती है। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनकी मां ने हौसला नहीं बढ़ाया होता तो वे कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पातीं।

बता दें कि जया प्रदा ने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही हिट फिल्में नहीं दी हैं, बल्कि तेलुगू फिल्मों में भी अभिनेत्री का सिक्का चलता था। जया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तेलुगू माध्यम से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी और फिल्म की आगे की पढ़ाई हैदराबाद से की थी। वे 70 से लेकर 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल थीं, जो उस वक्त सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थीं। जया ने हिंदी के साथ 7 अलग-अलग भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं और हिंदी और साउथ के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है।

# 'मर्दानी 3 को लेकर बोलीं मल्लिका प्रसाद, समाज खुद अपने दुश्मन गढ़ता है, अम्मा उसी सिस्टम की देन है

**मुंबई।** बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'मर्दानी 3' का बोलबाला है; फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी ने हमेशा ऐसे मुद्दों को छुआ है जिन पर आमतौर पर लोग बात करने से कतराते हैं। इसी कड़ी में 'मर्दानी 3' में खलनायिका 'अम्मा' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद ने अपनी राय साझा की। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा समाज खुद अपने दुश्मन गढ़ता है। इसके अलावा, उन्होंने अपने किरदार के बारे में भी खुलकर बात की। मल्लिका प्रसाद ने अपने किरदार को लेकर कहा, ''अम्मा को सिर्फ बुरा समझना आसान है, लेकिन उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अम्मा अकेले में पैदा हुई कोई शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि वह उस समाज का नतीजा है, जहां लगातार अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण देखने को मिलता है। जब किसी इंसान से बार-बार उसका हक छीना जाता है और उसे न्याय नहीं मिलता, तो वही सिस्टम धीरे-धीरे उसे कठोर और खतरनाक बना देता है। अम्मा भी उसी सिस्टम के भीतर रहकर काम कर रही है, जिसने कभी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मल्लिका ने कहा, ''यह बात थोड़ी डराने वाली जरूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा समाज खुद अपने दुश्मन तैयार करता है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी नाइंसाफी, लोगों की अनदेखी और सिस्टम की नाकामी मिलकर ऐसे किरदारों को जन्म देती हैं। अम्मा उसी टूट हुए भरोसे और छीने गए।

# जुड़वां बच्चों के माता-पिता बनने पर रामचरण और उपासना बोले, हम धन्य हुए

**हैदराबाद।** फिल्म आरआरआर फेम अभिनेता राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। इनमें एक बेटा और एक बेटी है। रामचरण के पिता और सुपरस्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। इस मौके पर राम चरण और उपासना ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। साल 2023 में राम चरण और उपासना की पहली संतान बेटी क्लिन कारा कोनिडेला पैदा हुई थी। उपासना ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अक्टूबर 2025 में घोषित की थी। राम चरण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'तीन बच्चों का आशीर्वाद मिलना मुझे बहुत कृतज्ञ महसूस कराता है। मैं अपने सभी प्रशंसकों, प्रियजनों और शुभचिंतकों का दिल से आभारी हूं, जो हर पल हमारे साथ खड़े रहे और हमें सपोर्ट दिया।' `उपासना ने भावुक होकर कहा, 'आज मैं तीन बच्चों की मां बनकर बहुत धन्य महसूस कर रही हूं, ठीक वैसा ही जैसा हमने सोचा था। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों की परवरिश ऐसे करें जो मजबूत भी हों और विनम्र भी। उन्हें पता हो कि विशेषाधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है।' एक बार फिर दादा बने चिरंजीवी ने पोस्ट किया, 'अत्यंत खुशी और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि राम चरण और उपासना को जुड़वां बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।'

## विदेश में रहने वाले भारतीय भी कर सकेंगे इन्वेस्ट, एनआरआई की निवेश लिमिट 24 फीसदी हुई

**नई दिल्ली।** भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार रविवार के दिन लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में केंद्रीय मंत्री ने नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (एनआरआई) और दूसरे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय लिस्टेड कंपनियों में व्यक्तिगत निवेश की सीमा को दोगुना करने का ऐलान किया है। अब तक ऐसा होता था कि एक अकेला एनआरआई किसी कंपनी के पेड-अप कैपिटल का 5-10 फीसदी तक मालिक हो सकता था। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, उसके तहत इस लिमिट को बढ़ाकर अब 10 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी एनआरआई के लिए कुल लिमिट बढ़ाकर 24 फीसदी करने का ऐलान किया गया।

पहले कई एनआरआई निवेशकों को मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या खास एनआरआई रूट से भारतीय इक्विटी में निवेश करना पड़ता था। अब इसमें सुधार किया गया है, जिसके बाद एनआरआई और विदेशी नागरिकों सहित विदेशी निवासियों को एक रेगुलेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत सीधे भारतीय स्टॉक में निवेश करने की इजाजत मिलेगी। इसका मकसद घरेलू मार्केट में एक्सेस को आसान बनाना और भागीदारी को बढ़ाना है।

इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की है कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को नॉन-इंडिया कमाई पर राहत मिलेगी। यह विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

वहीं, व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और विदेश यात्रा टूर पैकेज पर टीसीएस को 5 प्रतिशत/20 प्रतिशत से घटाकर 2 फीसदी किया गया है।

दूसरी ओर, इनकम टैक्स की बुनियादी संरचना पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केवल मामूली शुल्क देना होगा। रिटर्न फाइल करने की तारीखों को भी अलग-अलग किया गया है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले लोग पहले की तरह 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करेंगे। वहीं जिन कारोबारों का ऑडिट नहीं होता और ट्रस्ट्स को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए यह भी कहा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाला ब्याज अब इनकम टैक्स से मुक्त होगा। साथ ही इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा।

## बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन, लोग बोले-चुप रहना कोई विकल्प नहीं

**वॉशिंगटन।** बांग्लादेश में चुनाव से पहले हालात चिंतापूर्ण बने हुए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चरम पर है। हालात को लेकर पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। इस बीच हिंदू अमेरिकियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर टारगेटेड हमलों पर विरोध दर्ज कराया है।

अमेरिका के कई शहरों में शांतिपूर्ण रैलियां और प्रार्थना सभाएं की गईं। लोगों ने अमेरिका में कानून बनाने वालों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की।

प्रिंसटन, लॉस एंजिल्स, शिकागो, बे एरिया, डेट्रॉइट और टैम्पा समेत कई शहरों में प्रदर्शन की खबरें आईं। रैली के आयोजकों ने कहा कि मिलकर किए गए विरोध प्रदर्शनों का मकसद जागरूकता बढ़ाना और जवाबदेही तय करने पर जोर देना था।

प्रिंसटन की एक रैली में एक प्रवक्ता ने कहा कि लोग बांग्लादेशी हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के समर्थन में इकट्ठा हुए थे, जो बांग्लादेश में नरसंहार से गुजर रहे हैं और पिछले साल से 3,000 से ज्यादा हमले होने का दावा किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब बोलने का समय है। अब रुकने का समय है। डेट्रॉइट में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को क्रमिक नरसंहार बताया और कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और समर्थकों से कानून बनाने वालों को बुलाने, लोकल स्तर पर एकजुट होने और वॉशिंगटन के एक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

9 फरवरी को वॉशिंगटन में कांग्रेस की सार्वजनिक सुनवाई तय की गई है। लॉस एंजिल्स में प्रवक्ता ने प्रार्थना के साथ नागरिकों से एक्शन की अपील भी की। एक स्पीकर ने भीड़ से कहा, 'प्लीज चुप न रहें।' उत्तर अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन से जुड़े एक शख्स ने कहा कि आयोजकों ने लोगों को चुने हुए अधिकारियों से संपर्क करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन बनाई है। एफआईए-शिकागो और नेशनल इंडिया हब ने कहा, 'मासूम हिंदुओं पर सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान के कारण बेरहमी से हमला किया जा रहा है। चुप्पी और निष्क्रियता सिर्फ नरसंहार को बढ़ावा देती है।'

एफआईए-शिकागो और नेशनल इंडिया हब ने इलिनोइस के शॉमबर्ग में एक प्रदर्शन आयोजित किया था। आयोजकों ने कहा कि बोस्टन, ह्यूस्टन और लॉस एंजिल्स में भी इसी तरह के कार्यक्रम हुए थे और फरवरी में अमेरिकी कैपिटल में कांग्रेस की सुनवाई होनी है। हिंदूपैक्ट समेत मानवाधिकार और हिंदू वकालत करने वाले समूह के एक गठबंधन ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों का मकसद बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की बुरी हालत को दिखाना और पॉलिसी पर ध्यान दिलाना था।

## वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ आज से शुरू होगी

**बीजिंग।** वर्ष 2026 छुनयुन यानी वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ 2 फरवरी से शुरू होगी और 13 मार्च को खत्म होगी, जो 40 दिनों तक चलेगी। दिल को छू लेने वाले सफर का सीजन अब शुरू होने वाला है।

यह एक वसंत महोत्सव यात्रा है, जिसमें 'एक्स्ट्रा-लॉन्ग' 9-दिन की छुट्टी होगी। रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर लौटने और घूमने-फिरने की मांग से वसंत महोत्सव के दौरान अंतर-क्षेत्रीय प्रवाह करने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड तोड़कर 9.5 अरब होने की उम्मीद है।

इनमें, सेल्फ-ड्राइविंग ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य तरीका बना रहेगा, जो लगभग 80% होगा। रेलवे और सिविल एविएशन पैसेंजर वॉल्यूम के क्रमशः 54 करोड़ और 9.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

## बलूच विद्रोहियों के हमलों में 80 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत

**क्वेटा।** बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान प्रांत में सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद विरोधी यूनिट्स के जवानों समेत 80 से ज्यादा लोग मारे गए। बीएलए ने इस हमले को 'ऑपरेशन हेरोफ फेज-2' बताया है। बीएलए के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने एक बयान में कहा कि ये सिलसिलेवार हमले लगभग दस घंटे तक चले और बलूचिस्तान के कई जिलों में किए गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में उन जगहों को निशाना बनाया गया, जिन्हें समूह ने प्रमुख सुरक्षा, सैन्य और प्रशासनिक ठिकाने बताया है। बीएलए ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा, नोशकी, मस्तुंग, दलबांदिन, कलात और कई अन्य कस्बों में हमला किया। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इन इलाकों को पाकिस्तानी राज्य के महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। अपने बयान में बीएलए ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के कम से कम 84 सदस्य मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। समूह ने यह भी दावा किया कि हमलों के दौरान 18 सुरक्षाकर्मियों को बंदी बना लिया गया। आतंकवादी संगठन ने यह भी दावा किया कि 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर या तो कब्जा कर लिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। इनमें कथित तौर पर सरकारी दफ्तर, बैंक और जेल शामिल थे। इसके अलावा, संगठन ने दावा किया कि इस सिलसिलेवार हमले के तहत 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। बीएलए ने यह भी आरोप लगाया कि उसके लड़ाके कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब रहे और ऑपरेशन के दौरान कुछ इलाकों पर सीमित समय के लिए नियंत्रण का दावा किया। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने कथित तौर पर एक रिहायशी परिसर पर हमला किया, जहां मजदूर ठहरे हुए थे। बताया गया है कि पीड़ित तहसील जहरी के दो परिवारों के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्वादर की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग मारे गए, जबकि लगभग 10 अन्य घायल हो गए। इस बीच, तुर्बत से मिली खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने तुर्बत जिले के फुलाबाद के नागरिक इलाकों में मोर्टार के गोले दागे। कथित तौर पर गोलाबारी में एक 15 साल का लड़का मारा गया। हमले में एक पांच साल का बच्चा और दो महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई। फुलहाबाद में गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर इलाके में घरों को गिराना शुरू कर दिया था, जिससे क्षेत्र में जारी हिंसा के बीच तनाव और बढ़ गया।

## बांग्लादेश में चुनाव से पहले बढ़ते अपराध, जमात कार्यकर्ताओं ने बीएनपी कार्यालय में की तोड़फोड़

**ढाका।** बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच दिनाजपुर जिले के नवाबगंज उपजिला में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक चुनावी अभियान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, यह घटना दिनाजपुर-6 संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पुतिमारी यूनियन के डोलारदरगा इलाके में स्थित बीएनपी के चुनाव कार्यालय में हुई। इस संसदीय क्षेत्र में बीरमपुर, नवाबगंज, घोराघाट और हकीमपुर उपजिलाएं शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हमला किया, कुर्सी-टेबल तोड़ दिए और बैनर व चुनाव प्रचार सामग्री फाड़ दी। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद बीएनपी के दो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किए जाने की भी सूचना है। नवाबगंज थाना प्रभारी (ओसी) नूर आलम सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि इससे पहले दिन में बीएनपी के स्थायी समिति सदस्य और सांसद पद के उम्मीदवार डॉ. एज़ेडएम ज़ाहिद हुसैन के समर्थकों ने पार्टी के चुनाव चिह्न 'धान की

बालियां' के समर्थन में एक जुलूस निकाला था। ओसी के अनुसार, मग़रिब की नमाज़ के बाद जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार अनवरुल इस्लाम के समर्थकों ने बीएनपी कार्यालय के पास सड़क किनारे एक चुनावी सभा शुरू की। इस दौरान प्रचार में इस्तेमाल किए जा रहे माइक्रोफोन की आवाज और उपयोग को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि जमात कार्यकर्ताओं ने बीएनपी के दो कार्यकर्ताओं पर हमला किया और चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की। घटना के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उपजिला निर्वाही अधिकारी जिलूर रहमान ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), पुलिस और अंसार के जवानों को तैनात किया गया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले देशभर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले इसी महीने चुनाव प्रचार शुरू होने के दौरान बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को लेकर अप्रत्यक्ष चेतावनी दी थी और मतदाताओं से उन दलों का समर्थन न करने की अपील की थी, जिन पर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का सहयोग करने का आरोप है। बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने ठाकुरगांव जिले के बीडी हाई स्कूल मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की थीं। वे ठाकुरगांव-1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' के अनुसार, उन्होंने कहा था।

## ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत कर रहा है : ट्रंप

**वाशिंगटनँ।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर से कहा कि अगर बातचीत से कोई नतीजा निकलता है तो ठीक, नहीं तो आगे क्या होगा, यह बाद में देखा जाएगा। ट्रंप ने कहा, 'पिछली बार जब उन्होंने बातचीत की थी, तो हमें उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना पड़ा था। आपको पता है, वह काम नहीं किया। फिर हमने इसे दूसरे तरीके से खत्म किया, और हम देखेंगे कि क्या होता है।' ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ने ईरान की ओर एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेजा है। उन्होंने कहा कि यह बेड़ा उस बेड़े से भी बड़ा है, जो पहले वेनेजुएला के पास तैनात किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान से बातचीत के दौरान अमेरिका अपने सैन्य योजनाओं की जानकारी खाड़ी देशों के सहयोगियों को भी नहीं दे सकता। ईरान से जुड़े संभावित अमेरिकी दखल के प्लान के बारे में खाड़ी देशों के सहयोगी अंधेरे में हैं, इस रिपोर्ट्स पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम उन्हें प्लान नहीं बता सकते। अगर मैंने उन्हें प्लान बताया, तो यह लगभग उतना ही बुरा होगा जितना आपको प्लान बताना – यह असल में और भी बुरा हो सकता है।' इससे पहले ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। लारीजानी का यह बयान उस बैठक के बाद आया, जिसमें उन्होंने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस बैठक में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

## बांग्लादेश में जनवरी में मॉब किलिंग और हिरासत में हुई मौत के मामले में दोगुनी बढ़ोतरी

**ढाका।** बांग्लादेश में हिंसा के बढ़ते मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। हाल ही में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि चुनाव के दिनों तक भारी हिंसा बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश में जनवरी में भीड़ की हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम पिटाई से होने वाली मौतों की संख्या पिछले महीने के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही जेल में होने वाली मौतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। देश में राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे कानून-व्यवस्था और पूरे मानवाधिकार की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। मानवाधिकार सांस्कृतिक फाउंडेशन (एमएसएफ) की जारी हर महीने की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में भीड़ के हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए, जबकि दिसंबर 2025 में ऐसी 10 मौतें रिपोर्ट की गई थीं। शनिवार को जारी रिपोर्ट में जनवरी में मानवाधिकार की स्थिति को खतरनाक रूप से हिंसक और जटिल बताया गया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भीड़ की हिंसा के खिलाफ सरकार की तरफ से सुनिश्चित और साफ कार्रवाई न होने से सजा से बचने का ट्रेंड बढ़ा है। एमएसएफ ने कहा कि द डेली स्टार ने बताया कि इससे अपराधियों को बढ़ावा मिला है और जस्टिस सिस्टम में लोगों का भरोसा कम हुआ है। रिपोर्ट में इन घटनाओं को कानून के राज से लोगों के भरोसे में कमी का साफ संकेत बताया गया है। भीड़ के द्वारा की गई हत्या के अलावा, रिपोर्ट में देश भर में मिली अनजान लाशों की संख्या में बढ़ोतरी भी बताई गई है। जनवरी में कुल 57 लाशें मिलीं, जबकि दिसंबर में यह संख्या 48 थी। वहीं कस्टडी में हुई मौतें भी एक बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने आईं। जनवरी में जेल कस्टडी में मरने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जबकि पिछले महीने यह संख्या नौ थी। इसके अलावा, खबर है कि दो लोगों की मौत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कस्टडी में हुई। एमएसएफ ने इन मौतों के लिए मेडिकल लापरवाही, अमानवीय हालात और जेल मैनेजमेंट में सिस्टम की कमियों जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया। 13वें राष्ट्रीय चुनाव के पास आने के साथ रिपोर्ट में चुनाव से जुड़ी हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई। जनवरी के दौरान, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी झड़पों में चार लोगों की जान चली गई और 509 दूसरे घायल हो गए। यह दिसंबर के मुकाबले काफी बढ़ोतरी थी, जब चुनाव से जुड़ी सिर्फ एक मौत दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में एक और चिंताजनक ट्रेंड बताया गया ।

## अमेरिका सरकार की विशेष प्रतिनिधि वेनेजुएला पहुंचीं, तय होगी आगे की रूपरेखा

**काराकास।** वेनेजुएला के विदेश मंत्री ईवान गिल ने बताया है कि अमेरिका सरकार की विशेष प्रतिनिधि लौरा डोगू वेनेजुएला पहुंच गई हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच चल रहे वर्किंग एजेंडा का हिस्सा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईवान गिल ने यह जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत का मकसद आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर आगे की रूपरेखा तय करना है। साथ ही, जो मतभेद पहले से मौजूद हैं, उन्हें कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर चल रही है। यही सिद्धांत दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करते हैं। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की अगुवाई में चल रही कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका के समर्थन से एक व्यवस्था बनने के बाद वेनेजुएला से तेल का निर्यात फिर से शुरू हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के मौजूदा हालात में वहां का नेतृत्व अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं। ट्रंप के मुताबिक, जल्द ही कई देश वेनेजुएला से तेल लेना शुरू करेंगे और इसमें अमेरिका की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है और वे तेल लेना शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अब तक यह योजना बिना किसी बड़ी अड़चन के आगे बढ़ी है और सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि इस योजना में कौन-कौन से देश शामिल होंगे, तेल का समझौता किस तरह का होगा, तेल कब से निर्यात होगा और उसकी कीमत क्या तय की जाएगी।

## बढ़ते तनाव के बीच ईरान बोला- अमेरिका से बातचीत की तैयारी आगे बढ़ रही है

**काहिरा।** ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'बातचीत के ढांचे के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।' लारीजानी का यह बयान उस बैठक के बाद आया जो उन्होंने शुक्रवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की। इस बैठक में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी।

यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा (जिसकी अगुवाई विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन कर रहा है) ईरान की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के अनुसार, यह बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। इससे दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, हालांकि वाशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से कूटनीति की संभावना भी जताई है। शुक्रवार को इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि अमेरिकी गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस डेल्बर्ट डी. ब्लैक ने रेड सी में स्थित इलात बंदरगाह पर एक नियमित ठहराव किया। यह अमेरिका और इजरायल के बीच जारी सैन्य सहयोग को दर्शाता है।

इसी दिन ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तेहरान को सीधे एक समय सीमा दी है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया। शनिवार को फॉक्स न्यूज की संवाददाता जैकी हेनरिक ने 'एक्स' पर लिखा कि उन्होंने ट्रंप का साक्षात्कार लिया है, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका बातचीत जारी रखना चाहता है और परिणाम हासिल करने की उम्मीद करता है। उन्होंने यह भी बताया कि वाशिंगटन ने अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों को ईरान से जुड़े अपने कदमों की जानकारी नहीं दी है।

तेहरान ने पहले ही संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब बातचीत निष्पक्ष हो और किसी तरह के दबाव या धमकी के बिना की जाए। इसी बीच, ईरान के सेना प्रमुख आमिर हातामी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका कोई भी गलती करता है, तो इससे उसकी अपनी सुरक्षा के साथ-साथ इजरायल और पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

उधर, यमन के एक सैन्य सूत्र ने सिन्हुआ को बताया कि हूती समूह ने क्षेत्रीय तनाव के बीच अपनी युद्ध तैयारी बढ़ाने के लिए कई सैन्य कदम उठाए हैं, जिसमें ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की आशंका भी शामिल है।

# बजट 2026: सशस्त्र बलों को मिलेंगे नए फाइटर जेट, युद्धपोत और विशेष सैन्य वाहन

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। इस वर्ष के बजट में सशस्त्र बलों के पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं, पिछले साल यह राशि 1.80 लाख करोड़ रुपए थी। यानी इस साल इस मद में करीब 24 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। दरअसल, इस रकम से भारतीय सेनाओं के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट, आधुनिक हथियार, युद्धपोत, पनडुब्बियां, ड्रोन, यूएवी और विशेष सैन्य वाहन खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण अब जरूरत बन चुका है। सरकार ने इस बार साफ तौर पर स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। 1.39 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75 प्रतिशत, घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए तय किया गया है।

इसमें निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि देश में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और कई सहायक उद्योगों को फायदा मिलेगा। दरअसल रक्षा क्षेत्र को इस बार कुल केंद्रीय बजट का 14.68 प्रतिशत हिस्सा मिला है, जो किसी भी मंत्रालय को मिलने वाला सबसे बड़ा आवंटन है। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बीते साल 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस साल सैन्य आधुनिकीकरण पर खास जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह बढ़ा हुआ बजट देश की सैन्य तैयारियों को सुदृढ़ करने, रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीकी विकसित करने पर भी फोकस रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस राशि से आधुनिक हथियार प्रणालियों, नई तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद को गति मिलेगी और भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी सेनाएं और अधिक तैयार होंगी। राजस्व मद के तहत रक्षा बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1.58 लाख करोड़ रुपए ऑपरेशनल तैयारियों और रखरखाव पर खर्च होंगे। इससे जरूरी स्पेयर पार्ट्स, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों की नियमित जरूरतें पूरी होंगी। डीआरडीओ के बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है। इसले रक्षा अनुसंधान को नई रफ्तार मिलेगी। डीआरडीओ का बजट बढ़ाकर 29,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें से बड़ी राशि नई तकनीक, रिसर्च और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास पर खर्च होगी। रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित बजट को तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप रक्षा मंत्रालय को दिया गया यह बजट आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर केंद्रित है। साथ ही, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया है।

## विकसित भारत का रोडमैप है केंद्रीय बजट: केशव प्रसाद मौर्य

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को विकसित भारत का रोडमैप बताया।

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 गांव-गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन और किसानों की आय में वृद्धि को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह गरीबों, महिलाओं, उत्तम स्वास्थ्य, कृषि विकास, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित बजट है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण इस बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह

पीएम मोदी की गारंटी वाला बजट है। यह विकसित भारत का रोडमैप है। यह गरीब कल्याण तथा समग्र विकास पर केंद्रित बजट है। यह सर्व समावेशी बजट है। इसमें महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, और सर्व समाज के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। यह समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 युवा और महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा शिक्षा-स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

## संक्षिप्त खबर

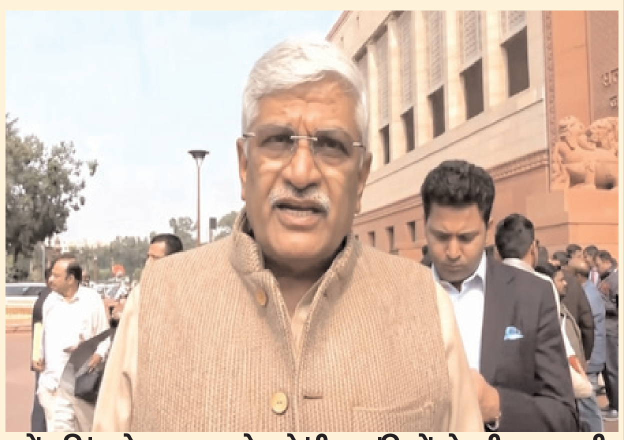

### गजेंद्र सिंह शेखावत समेत केंद्रीय मंत्रियों ने की बजट की सराहना, बोले विकसित भारत को मिलेगी नई दिशा

**नई दिल्ली।** केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बजट को अहम बताते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में हमें नई दिशा मिलेगी। इसी को देखते हुए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। 2014 के बाद से लगातार जिस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, उसे पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी दिनों में काफी अहम साबित होने जा रहा है। उन्होंने रविवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम क्रमबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ा रहा है। हमारे देश की आर्थिक दर बढ़ती रहे। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस बजट में हमने जनकांक्षाओं को भी शामिल किया है। इस बजट में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। खासकर, एमएसएमई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, भारत में मैन्युफैक्चिरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पर्यटन पर भी विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। नेशनल हॉस्पिटैलिटी बनाने की भी बात कही गई है। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेद्र यादव ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। शहरों के बुनियादी विकास के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में ग्रीन ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बॉयोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के मकसद से काम कर रहे हैं। हम ग्रीनिंग को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने चीता का संरक्षण करने के लिए दुनियाभर में एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया हुआ है। दुनिया के 97 देश इसके सदस्य हैं। इस बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सम्मेलन होगा। केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, 'दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। चाहे आप नॉर्थ-ईस्ट जाएं, बिहार या बंगाल जाएं, आपको यूपी से होकर जाना पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो देश विकसित होता है। अगर यूपी की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो देश का औसत बेहतर होता है। अगर यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो देश का पूरा सिस्टम अच्छे से काम करता है। इसके उलट, अगर यूपी की प्रति व्यक्ति आय या विकास खराब है तो देश की हालत खराब होती है। संक्षेप में, देश की प्रगति उत्तर प्रदेश के विकास से बहुत करीब से जुड़ी हुई है।'

### पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड की तैनाती के फैसले से संत-समाज में खुशी की लहर

**अयोध्या।** फरवरी की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का नौवां बजट पेश कर दिया है, जिसमें कृषि, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। केंद्रीय बजट में 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 प्रशिक्षित गाइड की तैनाती की घोषणा पर संत-समाज और अयोध्या में तैनात प्रशिक्षित गाइड ने खुशी जाहिर की है। केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए बजट पर साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने कहा, 'ये बजट सराहनीय और साधुवाद का बजट है। बजट में जन साधारण लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है, खासकर युवाओं के लिए और कृषि से जुड़े लोगों के लिए ये बजट खुशियां लेकर आया है। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और सबसे खास बात है कि 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 प्रशिक्षित गाइड की तैनाती की बात कही गई है और ये युवाओं को रोजगार देने वाला और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला काम है।'

## महाराष्ट्र को केंद्रीय करों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे: मुख्यमंत्री फडणवीस

**मुंबई।** महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय करों से महाराष्ट्र को 98,306 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसके अलावा, बजट के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 12,355 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए हैं।उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, महाराष्ट्र को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।उन्होंने कहा कि पुणे-हैदराबाद कॉरिडोर से मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे महानगर क्षेत्र और नागपुर महानगर क्षेत्र के विकास केंद्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 5 वर्षों में विकास केंद्रों के लिए 5000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। फडणवीस ने कहा कि 12,355 करोड़ रुपए की कुल धनराशि में से महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क परियोजना को 378.38 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय परियोजना को 167.28 करोड़ रुपए, समावेशी विकास के लिए आर्थिक क्लस्टर को 283.77 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र तृतीयक देखभाल और चिकित्सा शिक्षा विकास कार्यक्रम को 385.78 करोड़ रुपए, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की सौर ऊर्जा को 207.10 करोड़ रुपए, कृषि और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना को 646.24 करोड़ रुपए, मानव विकास के लिए कौशल और व्यावहारिक ज्ञान परियोजना को 313.65 करोड़ रुपए, जिलों में संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए 240.90 करोड़ रुपए, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर को 6103 करोड़ रुपए, मुंबई मेट्रो को 1702 करोड़ रुपए, एमयूटीपी 3 को 462 करोड़ रुपए, एमएमआर में हरित गतिशीलता को 155.32 करोड़ रुपए, समृद्धि राजमार्ग पर आईटीएस को 680.79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

## बजट तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है: चंद्रबाबू नायडू

**अमरावती।** आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे 'संतुलित' और 'दूरदर्शी' बताया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट 2026-27 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई दी। कुप्पम में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। टीडीपी अध्यक्ष का मानना है कि यह बजट आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह बजट राज्य सरकार को

उन मुद्दों पर और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में मदद करेगा, जिन पर वह ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति को और अधिक समर्थन देगा। राज्य सरकार पहले ही एमएसएमई पर काफी ध्यान केंद्रित कर चुकी है, और उन्हें और मजबूत करने का अवसर है। बजट को दिशा और गति प्रदान करने वाला बताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह एआई सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों और अगले स्तर के सुधारों को आवश्यक बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट नवीकरणीय ऊर्जा और एक ग्रिड राष्ट्र पर केंद्रित है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इसे अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। यह जीवन स्तर में सुधार और जीवन को सुगम बनाने में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से राज्य को लाभ होगा। तिरुपति और अमरावती भी हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे। बेंगलुरु-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पलमनेर, चित्तूर और अन्य क्षेत्रों को कवर करेगा। ये तीनों हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेंगे और हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों को आपस में मिलाएंगे।

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल रेयर अर्थ कॉरिडोर में भी शामिल किया गया है। इससे बहुमूल्य भारी खनिजों के खनन और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में उनके उपयोग का अवसर मिलेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि आईएसएम 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कपड़ा क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे आंध्र प्रदेश को काफी लाभ होगा।

## केंद्रीय बजट पर विपक्ष का निशाना, 'निराशाजनक और निंदनीय' करार

**लखनऊ।** केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने बजट को आम जनता से कटा हुआ, पूंजीपतियों के पक्ष में और गरीब-मध्यम वर्ग की उम्मीदों को तोड़ने वाला करार दिया है। विपक्षी नेताओं ने शेयर बाजार से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा और किसानों तक हर मोर्चे पर बजट को विफल बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पेश होते ही तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्?होंने कहा, 'आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम।' उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगा? हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 (एक बंटे बीस) का बजट मानते हैं क्योंकि वो पांच प्रतिशत लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट, अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। भाजपा का बजट, भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता-बही होता है। अखिलेश यादव ने बजट 2026 को लेकर कहा कि इस बजट में न आम जनता का जिक्र है न फ़िक्र। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना, 'टैक्स-शोषण' है। ?उन्होंने आगे कहा कि अमीरों के काम-कारोबार और घूमने-फिरने पर छूटें दी गई हैं, लेकिन बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की

उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। ?शोषित, वंचित, ग़रीब व्यक्ति जहां था, उससे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसकी चादर में पैबंद लगाने की जगह, उसे और चिथड़ा कर दिया है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा शाब्दिक औपचारिकता तक सीमित होकर रह गई है। उन्?होंने कहा कि ?किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, और छोटे दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बजट को 'निराशाजनक' और 'निंदनीय' बताया है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद में पेश बजट को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'देश के संसद में आज केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के संबंध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े-बड़े हैं, किंतु जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे ना हों तो बेहतर होगा।

' मायावती ने कहा, 'इसीलिए सर्वसमाज के हित में केवल बातें ना हों बल्कि इनपर सही नीयत से अमल भी जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो केंद्र सरकार का बजट सत्ताधारी पार्टी की नीति व नीयत में चाल, चरित्र और चेहरे का आईना होता है, जिसमें यह झलक मिलती है कि सरकार की सोच वास्तव में गरीब व बहुजन-हितैषी होकर व्यापक देशहित की है या फिर पूंजीवादी सोच की पोषक और बड़े-बड़े पूंजीपति समर्थक है। मायावती ने कहा कि खासकर अपने भारत देश के संदर्भ में इस बात का भी विशेष महत्व है कि सरकार की नीति दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की है, तो उसके लिए सरकारी क्षेत्र को कितना महत्व देकर परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से क्या कार्य किया गया है। उन्होंने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा, संसद में आज पेश बजट को भी देखा जाना चाहिए कि कहीं यह बजट भी आया और गया की तरह परंपरागत रूप से मायूस करने वाला तो नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बजट पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह पूरी तरह दिशाहीन और आम जनता की उम्मीदों को तोड़ने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसे बुनियादी विषयों पर सरकार ने जनता को पूरी तरह निराश किया है। अजय राय ने आरोप लगाया कि मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत देने के बजाय यह बजट सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने वाला 'पूंजीवादी बजट' है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं से कटी हुई भाजपा सरकार का यह असली चेहरा है।

## बीफ विवाद: यूट्यूबर सायक चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज

**कोलकाता।** पार्क स्ट्रीट इलाके के एक रेस्तरां में मटन की बजाय बीफ परोसने का आरोप लगाने वाले यूट्यूबर सायक चक्रवर्ती अब कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं।

पुलिस ने रविवार को बताया कि जॉयराज भट्टाचार्जी नाम के एक व्यक्ति ने शनिवार रात पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में चक्रवर्ती के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, चक्रवर्ती पर साजिश रचकर दंगा भड़काने का आरोप है। उस व्यक्ति ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि मैंने एक खास इन्फ्लुएंसर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

शनिवार को, कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्थित एक लोकप्रिय बार-कम-रेस्तरां के एक कर्मचारी को यूट्यूबर को मटन के बजाय

बीफ परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी यूट्यूबर द्वारा शुक्रवार रात पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

वेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, उनके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में पेश किए जाने पर गिरफ्तार आरोपी शेख नासिरुद्दीन को जमानत नहीं मिली। पता चला है कि सायक शुक्रवार रात अपने दो दोस्तों के साथ मशहूर बार-कम-रेस्तरां ओलीपब गए थे। उनकी शिकायत के अनुसार, उन्होंने मटन स्टेक की एक प्लेट मंगवाई थी। हालांकि, उन्हें कथित तौर पर मटन के बजाय बीफ परोसा गया।

घटना के बाद, सायक ने घटना और रेस्तरां के वेटर और मैनेजर के साथ हुई कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

फेसबुक पर साझा किए गए वीडियो में सायक ने अपनी आपबीती सुनाई। वीडियो में वह कह रहे हैं कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने मटन ऑर्डर किया था, लेकिन रेस्टोरेंट के वेटर ने उन्हें बीफ परोस दिया।

## सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह बजट जरूरी: रामदास आठवले

**नई दिल्ली।** केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देने वाला है। यह सभी वर्गों-विशेषकर युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को न्याय देने वाला बजट है। आईएएनएस से बातचीत में केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बजट में छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है। मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में उचित राहत प्रदान की गई है। यह पूरी तरह से 'सबका साथ, सबका विकास' वाला बजट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के

बजट को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वे निराश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस अभी सत्ता में आने वाली नहीं है। इसीलिए वे हर बजट पर इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा कि यह निराशा का नहीं, बल्कि आशावादी और विकास करने वाला बजट है। यह देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बजट है। इस बजट में दिव्यांगजनों, दलितों और समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रावधान किया गया है। खड़गे के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। उन्हें शायद इस बजट की पूरी जानकारी ही नहीं है कि इसमें क्या-क्या है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूरदर्शी और संतुलित रोडमैप के रूप में सामने आया है। सरकार ने कृषि, एमएसएमई निवेश और निर्यात को विकास के चार मुख्य इंजनों के रूप में पहचान कर अर्थव्यवस्था को गति देने की ठोस योजना पेश की है। विशेष रूप से 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' के जरिए 1.7 करोड़ किसानों की उत्पादकता सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

# बजट 2026 में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का हुआ ऐलान, पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स को मिलेगा बढ़ावा

**नई दिल्ली।** केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत सहायता की घोषणा की है।

साथ ही सरकार ने बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया है, जिससे निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकारी बयान में कहा गया कि ये पार्क टेक्निकल टेक्सटाइल के विकास में भी सहयोग देंगे, जो औद्योगिक, चिकित्सा, रक्षा और बुनियादी ढांचा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण एक उच्च क्षमता वाला क्षेत्र है।

इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऐलान किया गया।

इसके पांच घटक होंगे, जिसमें नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टेक्स-ईको इनिशिएटिव और कौशल के लिए समर्थ 2.0 शामिल हैं।

समर्थ 2.0 एक एडवांस कौशल विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मूल्य श्रृंखला में उद्योग के लिए तैयार कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

सीआईआई पंजाब के चेयरमैन अमिन जैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी सारे ऐलान किए है। इसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, अधिक श्रम उपयोग वाले टेक्सटाइल के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाना और हेरिटेज टेक्सटाइल पार्क को दोबारा से विकसित करने की जो बात कही गई है। इससे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई फंड बनाने का ऐलान किया गया है। देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई टेक्सटाइल सेक्टर में है। इससे पूरे सेक्टर को फायदा होगा।

हाल में सरकार ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे देश के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए निर्यात के अवसर बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार का टेक्सटाइल क्षेत्र पर फोकस होने से देश में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

# बजट में हुए ऐलानों से देश का मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा: इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री

**नई दिल्ली।** इंडस्ट्री ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि इसमें एक स्थिर और व्यापक रूप से समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो नीतिगत निरंतरता, व्यापकता और लक्षित सुधारों के माध्यम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बॉडी आईसीईए ने कहा कि बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का ऐलान किया गया है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) का विस्तार किया गया है। यह देश में घरेलू आपूर्ति श्रृंख्लाओं और वैल्यू चेन को मजबूत बनाएगा।

आईसीईए ने भारत स्थित डेटा केंद्रों का उपयोग करके वैश्विक क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट की घोषणा का भी स्वागत किया, इसे एक दूरदर्शी उपाय बताया जो दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता प्रदान करता है।

आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, 'बजट 2026-27 निरंतरता, व्यापकता और लक्षित सुधारों के माध्यम से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग-आधारित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ईसीएमएस के विस्तार, आईएसएम 2.0 के समर्थन और क्लाउड और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहनों जैसे उपाय रणनीतिक इरादे और नीतिगत स्थिरता का एक मजबूत संकेत देते हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हुई तीव्र वृद्धि ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि साहसिक और निरंतर नीतिगत उपायों से क्या हासिल किया जा सकता है।

आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा कि वित्त मंत्री का आईएसएम 2.0 पर दिया गया बयान भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है।

उन्होंने आगे कहा, 'यह फैब-केंद्रित दृष्टिकोण से एक पूर्ण मूल्य-श्रृंखला रणनीति की ओर स्पष्ट विकास को दर्शाता है, जिसमें उपकरण, सामग्री, भारतीय बौद्धिक संपदा और आपूर्ति-श्रृंखला को मजबूत बनाना शामिल हैं। यह भारत के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक भागीदार से एक संरचनात्मक खिलाड़ी बनने के लिए महत्वपूर्ण है।'

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा कि बजट 2026-27 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, सुधारों और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर अपना जोर जारी रखा है, साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किए हैं।

केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई डेवलपमेंट फंड की स्थापना, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना और रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना शामिल है।

# एसटीटी में बदलाव से लंबी अवधि के निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन : बीएसई सीईओ

**मुंबई।** सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बदलाव से निवेशक शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही इससे बाजार में लिक्विडिटी में भी बढ़त होगी। यह जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के एमडी और सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति की ओर से रविवार को दी गई।

राममूर्ति ने बयान में कहा कि यह केंद्रीय बजट भारत को भविष्य के निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करता है। इससे पूंजीगत बाजार अधिक गहरे एवं ज्यादा संतुलित होंगे और यह देश की लंबी अवधि की आर्थिक प्राथमिकता के अनुरूप है। यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पूंजी निर्माण, राजकोषीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सेवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे प्रमुख विकास स्तंभों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, 'बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च से

पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।' मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल ने कहा कि यह बजट भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक मास्टरस्ट्रोक है। उन्होंने एक बयान में कहा, 'पूंजी बाजारों पर एसटीटी के प्रभाव के बारे में हमें यथार्थवादी होना चाहिए।

एसटीटी में वृद्धि और डिविडेंड सेट-ऑफ को हटाने से बाजारों में कमजोरी देखी जा रही है। इससे कई हाई-फ्रीक्वेंसी और आर्बिट्रेज ट्रेड अव्यवहार्य हो जाएंगे, जिससे अल्पावधि में बाजार की तरलता और लीवरेज पर दबाव पड़ेगा।' अग्रवाल ने आगे कहा, 'लेकिन विवेकपूर्ण 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ, दीर्घकालिक आय ही भारत के लिए असली हीरो है।' बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरधारकों को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है।

इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स पर कहा कि नए संरचना के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर प्रभावी रूप से 22 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक लेनदेन के लिए 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

# पोषक तत्वों से भरपूर केले का छिलका, सेहत के लिए वरदान

**नई दिल्ली।** केला हर घर में रोजाना खाया जाने वाला फल है। यह मीठा, पौष्टिक और तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है, लेकिन ज्यादातर लोग केला खाने के बाद उसका छिलका बिना सोचे-समझे कूड़े में डाल देते हैं। अब वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हो चुका है कि यह छिलका बेकार नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है।

केले की तरह ही इसके छिलके में भी कई ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की जानकारी के अनुसार, केले के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं। ये तत्व शरीर में जमा विषैले पदार्थों को निकालते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और कई बीमारियां दूर रहती हैं।

रिसर्च में सामने आया कि छिलके में गैलोकैटेचिन नाम का प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह तत्व शरीर को डिटॉक्स करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि छिलके में केले के गूदे से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके छिलके में फ्लेवोनोइड्स, टैनिन और सैपोनिन जैसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक कणों से मुकाबला करते हैं।

फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाकर कैंसर, दिल की बीमारी और समय से पहले बुढ़ापा जैसे रोगों का कारण बनते हैं। इसके अलावा, छिलके में मजबूत एंटीबैक्टीरियल शक्ति होती है। यह ई. कोलाई, साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोक्स जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। ये बैक्टीरिया पेट दर्द, दस्त, बुखार और संक्रमण पैदा करते हैं। साथ ही, यह दांतों और मसूड़ों के संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर भी असरदार है।

छिलके में गैलिक एसिड, फेरुलिक एसिड और कैटेचिन जैसे तत्व फंगस (फंगल इंफेक्शन) से भी लड़ते हैं। कुछ शोधों में यह भी देखा गया कि छिलके से बने नेचुरल कलर में भी एंटीबैक्टीरियल गुण बने रहते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि छिलका अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्मूदी, चाय, बेकिंग, या घरेलू फेस मास्क में भी इस्तेमाल लाभदायी है। अगर कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

# वित्त मंत्री ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया, आईएसएम 2.0 का भी ऐलान हुआ

**नई दिल्ली।** केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते अवसरों का फायदा उठाना है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके जरिए कोशिश इंडस्ट्री के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग सेक्टर को आने बढ़ाना है।

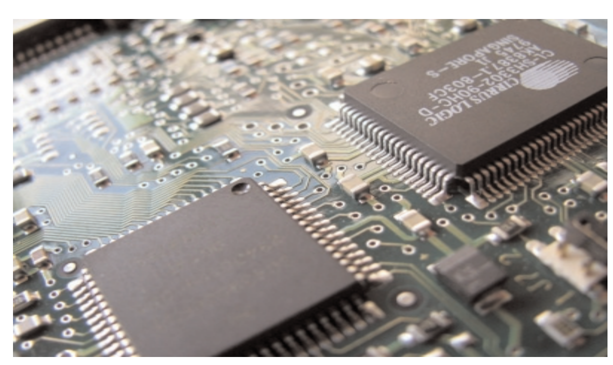

बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है। इसी आधार पर सरकार उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 की शुरुआत करेगी। भारत के सेमीकंडक्टर विकास की गति का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया है।' वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'हम प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के विकास के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,999 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (आईएसएम) को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं।'

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक समर्पित कोष की शुरुआत का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में रोजगार सृजित करना और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन देना है। श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख घटकों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्तावित किया गया है। पहला घटक - नेशनल फाइबर स्कीम है, जिसका लक्ष्य रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर्स के साथ-साथ मानव निर्मित और नए औद्योगिक युग के फाइबर्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

# केंद्रीय बजट 2026 भारत को एआई और डिजिटल सुपरपावर बनाएगा: दीपक शिकारपुर

**पुणे।** काइनेटिक कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर दीपक शिकारपुर ने केंद्रीय बजट 2026 को भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक अहम मोड़ बताया। उन्होंने दावा किया कि यह बजट देश को आत्मनिर्भरता और डिजिटल नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे ले जाने वाला है। दीपक शिकारपुर ने कहा कि वे पिछले 41 वर्षों से आईटी इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 1985 में आईटी इंडस्ट्री जॉइन की थी, तब आईटी का मतलब इनकम टैक्स हुआ करता था, लेकिन आज हम पूरी तरह से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डिजिटल वर्ल्ड के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हर तरफ डिजिटाइजेशन की चर्चा हो रही है। केंद्रीय बजट 2026 के शुरुआती पांच मिनटों में ही एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की घोषणा। इसके साथ ही चार राज्यों में रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिज) की खोज पर फोकस किया जाएगा। इससे आने वाले समय में भारत में

हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। शिकारपुर ने कहा कि वर्तमान में भारत का लगभग 90 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर चीन और ताइवान पर निर्भर है। यदि यह मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होने लगे, तो आत्मनिर्भर भारत मिशन को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। उन्होंने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किए गए प्रावधानों को भी बेहद अहम बताया। उनके अनुसार, एआई की मूल नींव डेटा साइंस पर टिकी है और यहीं पर डेटा सेंटर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दीपक शिकारपुर ने बताया कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करती हैं, तो उन्हें 20 साल की टैक्स हॉलीडे दी जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी राहत और आकर्षक पहल है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स को ग्रीन बनाने के लिए 40 प्रतिशत तक की ग्रांट देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह धारणा है कि डेटा सेंटर्स बहुत अधिक पानी और बिजली की खपत करते हैं, लेकिन यदि उन्हें हरित तकनीक की ओर प्रोत्साहित किया जाए, तो इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और यह पृथ्वी के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दीपक शिकारपुर ने छात्रों, शिक्षण संस्थानों और श्रोताओं से अपील करते हुए कहा कि भविष्य की नौकरियां डेटा सेंटर्स और जीसीसी में हैं। उन्होंने सुझाव दिया ।

## पीएकेभारत को उनकी परिस्थितियों में हराना बहुत मुश्किल है: मिचेल सेंटनर

**तिरुवनंतपुरम।** न्यूजीलैंड को भारत के हाथों ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में 46 रन से हार झेलनी पड़ी। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्वीकारा है कि टीम इंडिया को उनकी परिस्थितियों में हराना बहुत मुश्किल है। मिचेल सेंटनर ने कहा कि सीरीज हारने के बावजूद उनकी टीम ने कुछ सकारात्मक बातें सीखी हैं। मुकाबले के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जब आप पूरी सीरीज को देखते हैं, तो हमने बहुत सारी सकारात्मक बातें सीखी हैं। भारत एक बहुत अच्छी टीम है। मैंने यह शुरू में ही कहा था, और उनकी परिस्थितियों में उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। शायद हमने गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दीं, लेकिन कुल मिलाकर, यह मनोरंजक मैच था।' कीवी कप्तान का मानना है कि भारत के खिलाफ यह सीरीज न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद करेगी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जब आपको पूरी सीरीज में चुनौती मिलती है, तो यह हमेशा एक अच्छी बात होती है। आप अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों पर दबाव डालते हैं, और आप उससे ही सीखते हैं। इस नजरिए से, यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीरीज रही है। जाहिर है, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हर मैच से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। 'बॉलिंग यूनिट के लिए सीख पर, सेंटनर ने कहा, 'यह आसान नहीं है। एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर हमें बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ तरीके तलाशने होंगे, ऐसे खिलाड़ी जो चौकों और छक्कों से रन बटोरते हैं। शायद बात यह है कि बड़े ओवरों को 15-16 रन तक सीमित किया जाए, खासकर सपाट पिचों पर, यह समझते हुए कि 230 का स्कोर भी हासिल किया जा सकता है।' शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 271 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवरों में 225 रन पर सिमट गई।

## बजट 2026: खेलो इंडिया मिशन के तहत अगले एक दशक में रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करेगी सरकार

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र को रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के दृष्टिकोण से अहम माना है। उन्होंने अगले एक दशक में भारत के खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा, 'खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। वित्त मंत्री के अनुसार, खेलो इंडिया मिशन का मकसद टैलेंट को तराशने के साथ-साथ युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करना है। बजट के माध्यम से पेश खेलो इंडिया मिशन के तहत सरकार अगले 10 सालों में भारत को दुनिया के खेल मानचित्र पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। खेलो इंडिया मिशन को सरकार सिर्फ खेल, मनोरंजन या सेहत तक सीमित न रखकर इसे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुख्य जरिया बनाने जा रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर फायदा होगा।

खेलो इंडिया मिशन के तहत अब देश के छोटे गांवों और शहरों से खिलाड़ियों को खोजने का काम और तेज होगा। सरकार का लक्ष्य होनहार खिलाड़ियों की पहचान कर उनके रहने-खाने और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें ओलंपिक जैसे बड़े मंचों के लिए तैयार करना है।

खिलाड़ियों के साथ ही खेलो इंडिया मिशन के तहत सर्टिफाइड कोच, हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर और स्काउट्स को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। इससे कोचिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले खिलाड़ियों के लिए रोजगार का रास्ता खुलेगा।

सरकार खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए एक पेशेवर टीम तैयार करना चाहती है। इस वजह से फिजियोथेरेपिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक और डाइट विशेषज्ञ की मांग बढ़ेगी। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा।

खेलो इंडिया मिशन बड़े स्तर पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और इवेंट आयोजन करने वाली कंपनियों और युवाओं को साथ जोड़ेगा। इससे स्टेडियम के रखरखाव और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे।

'मेक इन इंडिया' के तहत अब भारत दुनिया के लिए खेल का सामान बनाएगा। बेहतरीन क्वालिटी के बैट और जूते तैयार किए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में भारी निवेश होगा और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।

भारत साल 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। 2036 ओलंपिक की दावेदारी के लिए भारत मजबूती से प्रयास कर रहा है। खेलो इंडिया मिशन के तहत उठाए जाने वाले कदम इन आयोजनों में देश की दमदार मौजूदगी के वाहक बनेंगे।

## विंटर ओलंपिक 2026: ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन कर्लिंग टाइटल के फेवरेट के तौर पर शुरुआत करेंगे

**मिलान।** मिलान-कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक में कर्लिंग की शुरुआत 4 फरवरी को मिश्रित डबल इवेंट से होगी और 22 फरवरी को महिला टीम गोल्ड मेडल मैच के साथ खत्म होगी। तीनों इवेंट, पुरुष टीम, महिला टीम और मिश्रित डबल्स, डोलोमिटिक आल्प्स में उत्तरी इटली के शहर कॉर्टिना डी'एम्पेजो के कॉर्टिना ओलंपिक स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह जगह 1956 के विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए बनाई गई थी। पुरुष और महिला टीम इवेंट्स 11 फरवरी को शुरू होंगे, जो पहले पुरुष राउंड-रॉबिन सेशन से शुरू होंगे। मेजबान देश होने के नाते, इटली ने तीनों इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा ओलंपिक मिश्रित डबल्स चैंपियन स्टेफानिया कॉन्स्टेंटिनी और अमोस मोसानर के नेतृत्व में इटली इस वर्ग की पसंदीदा टीमों में से एक है। पुरुषों के इवेंट में, स्वीडन, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। महिलाओं के इवेंट में, ब्रिटेन चार साल पहले बीजिंग में पोडियम पर टॉप पर रहा था, जबकि कनाडा ने 2025 वर्ल्ड कर्लिंग चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव किया था। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया की टीमों को भी बड़ा कंटेंडर माना जा रहा है, जिनके मैच अक्सर बहुत कम अंतर से तय होते हैं।

चीन पुरुषों और महिलाओं दोनों के इवेंट में टीमें उतारेगा। स्किप, शू जियाओमिंग, और वांग रुई, दोनों तीसरी बार ओलंपिक में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ओलंपिक में उनके अनुभव और नेतृत्व का टेस्ट फिर से होगा।

## मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए 125 के सीरीज के लिए मेन ड्रॉ का ऐलान

**मुंबई।** मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए 125 के सीरीज के पांचवें एडिशन के लिए मंच तैयार है, क्योंकि शनिवार को महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन (एमएसएलटीए) में मेन ड्रॉ सेरेमनी हुई, जिसमें टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई। यह टूर्नामेंट 2 से 8 फरवरी तक खेला जाएगा। मेन ड्रॉ सेरेमनी में भारतीय वाइल्ड कार्ड पाने वालीं श्रीवल्ली भामिदीपति, माया राजेश्वरन रेवती और वैष्णवी अडकर, साथ ही भारत की डबल्स खिलाड़ी रुतुजा भोसले मौजूद थीं। इस मौके पर एमएसएलटीए के सेक्रेटरी सुंदर अय्यर, जॉइंट सेक्रेटरी निखिल संपत और भारत की बिली जीन किंग कप कोच राधिका तुलपुले भी मौजूद थीं। जब 2 फरवरी को मेन ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे, तो भारतीय खिलाड़ी सुर्खियों में रहेंगे, जिसमें कई घरेलू टैलेंटेड खिलाड़ी मजबूत इंटरनेशनल विरोधियों का सामना करेंगे। भारत की नंबर 1 महिला सिंगल्स स्टार सहाजा यमलपल्ली का मुकाबला जापान की एरी शिमिजू से होगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाली श्रीवल्ली भामिदीपति पहले राउंड में एक क्वालिफायर से भिड़ेंगी, जबकि माया राजेश्वरन रेवती, जिन्हें भी वाइल्ड कार्ड मिला है, का मुकाबला थाईलैंड की लानलाना तारारुडी से होगा। महाराष्ट्र की नंबर 1 सिंगल्स खिलाड़ी वैष्णवी अडकर का मुकाबला ऑस्ट्रिया की लिली टैगर से होगा। एक और भारतीय वाइल्ड कार्ड, वैदेही चौधरी, अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस की तीसरी वरीयता प्राप्त लियोलिया जीनजीन के खिलाफ करेंगी। टूर्नामेंट से पहले अपनी अप्रोच के बारे में बताते हुए, पिछले एडिशन की सेमी फाइनलिस्ट माया राजेश्वरन रेवती ने कहा, 'पिछले साल मैं बिना किसी उम्मीद के आई थी और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं इस साल भी ऐसा ही करने जा रही हूं। मैं अभी भी युवा हूं और शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हो रही हूं। मेरे लिए, यह हर दिन बेहतर होने, फिट रहने, चोट से मुक्त रहने और बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में है।' भारतीय टेनिस कैलेंडर में टूर्नामेंट के महत्व पर जोर देते हुए, एमएसएलटीए के सेक्रेटरी सुंदर अय्यर ने कहा, 'हमारे लिए साल के इस समय यह टूर्नामेंट आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इवेंट हमें उन खिलाड़ियों की पहचान करने में मदद करता है जिन पर हमें भविष्य के इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। यह साल एशियाई खेलों के आने के कारण भी महत्वपूर्ण है, और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'यहां अर्जित रैंकिंग अंक पूरे साल खिलाड़ियों के पास रहते हैं, यही वजह है कि फरवरी का महीना चुना गया है। मुंबई में इस समय मौसम बहुत अच्छा है, और मैं एमएसएलटीए मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस शानदार फेडरेशन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी, जिसे एक स्टेडियम में बदल दिया गया है। एमएसएलटीए की ओर से, मैं सभी का स्वागत करता हूं।

## ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल: अल्काराज या जोकोविच, ईशान और अर्शदीप किसे चैंपियन बनाना चाहते हैं?

तिरुवनंतपुरम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल फाइनल का स्टेज तैयार है। रविवार को फाइनल मुकाबला 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच और अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की कोशिश में जुटे स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बीच होना है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्काराज का समर्थन किया है। बीसीसीआई द्वारा एक्स पर शेयर एक वीडियो में ईशान किशन ने कहा, 'मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि अल्काराज जीते क्योंकि मुझे लगता है कि वह जिस तरह से खेलता है, वह काफी हद तक हमारे खेलने के तरीके जैसा है। वह थोड़ा तेज है। जब भी कोई गैप होता है, तो वह उसे हिट करने की कोशिश करता है। वह देखता नहीं है, सब्र नहीं दिखाता है।

'किशन का मानना ??है कि अल्काराज का आक्रामक खेल और मौकों को भुनाने की इच्छा उसे बड़े मैचों में एक रोमांचक खिलाड़ी बनाती है। जोकोविच जैसे अनुभवी चैंपियन के खिलाफ भी वह बेहद असरदार है। भारतीय विकेटकीपर ने कहा कि अल्काराज अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके पक्ष में हूं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता को लेकर अलग सोच है। अर्शदीप चाहते हैं कि नोवाक जोकोविच खिताब जीते।

अर्शदीप ने कहा कि मैं आइसमैन (जोकोविच) को सपोर्ट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल दो पीढ़ियों के बीच एक बड़ा मुकाबला है, जिसमें अल्काराज और जोकोविच दोनों अपने-अपने ऐतिहासिक मुकाम को हासिल करने की कोशिश में हैं। मेलबर्न में जीत से 22 साल के स्पेन के इस खिलाड़ी का करियर का ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाएगा। वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतते हीं वह सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। स्पेन के ही राफेल नडाल ने 24 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अल्काराज नडाल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की जीत उनके लिए 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगी। इस जीत के साथ ही वह पुरुष या महिला हर वर्ग में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे।

## अनुराधा देवी थोकचोम: रिक्शा चालक पिता की बेटी ने देश के लिए जीता था 'स्वर्ण'

**नई दिल्ली।** मणिपुर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल के क्षेत्र के पावरहाउस के रूप में उभरा है। एथलीट न सिर्फ पारंपरिक खेलों बल्कि हर तरह के खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी राज्य से निकली एक बड़ा नाम अनुराधा देवी थोकचोम हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में बड़ा नाम बनाया है। अनुराधा देवी थोकचोम का जन्म 2 फरवरी 1989 को तौबुल, मणिपुर में हुआ था। अनुराधा की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता, थोकचोम चुरामणि, एक रिक्शा चालक थे। अनुराधा तीन भाई-बहन हैं। उनके बड़े भाई फुटबॉल के खिलाड़ी थे। उनका परिवार खेती और मछली पालन से भी जुड़ा था।मणिपुर में हॉकी को लेकर बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहा है। व्यापक तौर पर फुटबॉल खेली जाती थी, लेकिन भाई-बहनों के मार्गदर्शन में अनुराधा ने बहुत कम उम्र में ही हॉकी स्टिक पकड़ ली। थोकचोम ने तोबुल यूथ क्लब में हॉकी खेलना शुरू किया और बाद में इम्फाल स्थित पोस्टीरियर हॉकी अकादमी मणिपुर में दाखिला लिया। 2006 की महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हुआ था। थोकचोम भारतीय टीम के लिए फॉरवर्ड के तौर पर खेलती थीं और 80 से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं। थोकचोम ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था, जहां भारतीय महिला टीम ने 36 साल के लंबे अंतराल के बाद क्वालीफाई किया था। 2014-15 की महिला हॉकी वर्ल्ड लीग में भारतीय टीम की जीत में उनके रोल के लिए कमेंटेटर्स ने उनकी तारीफ की थी, जहां वे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के लिए पांचवें स्थान पर रही थीं। वह 2013 में क्वालालंपुर में आयोजित एशिया कप में कांस्य और 2016 में सिंगापुर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण जीतने वाली टीम की सदस्य रही हैं। इस खिताबी जीत के बाद उन्होंने हॉकी को अलविदा कह दिया था। वर्तमान में वे भारतीय रेलवे के लिपिक विभाग में कार्यरत हैं।

## सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर दिया अपडेट

**तिरुवनंतपुरम।** भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में जीत के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर अपडेट दी। तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले घरेलू क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हो गए। उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। वह लगभग एक महीने से क्रिकेट से बाहर हैं। `टी20 विश्व कप की टीम में शामिल तिलक वर्मा की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'तिलक वर्मा अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। मैंने सुना है कि वह मुंबई में 2 और 4 फरवरी को दो मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि दो मैच काफी हैं। मैंने उनसे कल ही बात की थी। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सबकुछ शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही हमारे पास होंगे। वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मुझे लगता है कि वाशी भी अच्छा कर रहा है। उससे भी मेरी बात हुई है।

## प्रो रेसलिंग लीग 2026: विदेशी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास खेल की समझ बढ़ाता है, महाराष्ट्रं केसरी की मनीषा भानवाला का बयान

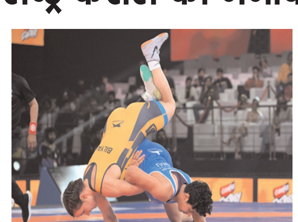

**नोएडा।** महाराष्ट्र केसरी की मनीषा भानवाला को दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ प्रो रेसलिंग लीग 2026 सेमीफाइनल के दौरान 57 किग्रा महिला कैटेगरी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फाइटर ऑफ द मैच चुना गया। अपनी टीम की हार के बावजूद, 28 साल की मनीषा ने कहा कि लीग बहुत कीमती है। यह एक्सपोजर और सीखने के मौके देती है। इससे भारतीय पहलवानों को एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे बड़े वैश्विक टूर्नामेंट की तैयारी करने में मदद मिलेगी। मनीषा ने एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जैसे ग्लोबल इवेंट्स की तैयारी में प्रो रेसलिंग लीग की अहमियत पर आईएएनएस से कहा, 'जब भी इंडिया में कोई मुकाबला होता है, तो हम सबके खिलाफ खेलते हैं, और इससे बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। हम विदेशी खिलाड़ियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं, तो वे ही हमारे सामने विपक्षी होते हैं। उनके साथ अभ्यास करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या करना है और कैसे करना है।' उन्होंने कहा, 'इस लीग में खेलने से हमें अपनी गलतियां पहचानने में मदद मिलती है और हमें यह आइडिया मिलता है कि हमें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। यह लीग बहुत फायदेमंद है।' अनुभवी और शीर्ष विदेशी पहलवानों के साथ रहने और उनसे सीखने के सवाल पर भानवाला ने कहा, 'ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं जानते, और हम उनसे सीखते हैं। हम समझते हैं कि किसके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है, इसलिए उनके साथ रहना बहुत फायदेमंद है। सब लोग साथ रहते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं, जो अच्छा लगता है।

## सूर्यकुमार यादव ने की वानिंदु हसरंगा की बराबरी, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

**तिरुवनंतपुरम।** भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2026 की शुरुआत दमदार रही है। बीते साल रनों के लिए जूझते दिखे सूर्यकुमार यादव विश्व कप से ठीक पहले फॉर्म में आ चुके हैं। फॉर्म में आते ही सूर्यकुमार रन मशीन विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं। साल 2025 की 22 पारियों में एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे सूर्यकुमार यादव ने 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज की दमदार शुरुआत की और पहले मैच में 22 गेंद पर 32 रन बनाए। इसके बाद दूसरे टी20 में 37 गेंद पर 82, तीसरे टी20 में 26 गेंद पर 57, चौथे टी20 में 8 गेंद पर 8, और पांचवें टी20 में 30 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। कुल 5 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद से उन्होंने 242 रन बनाए। भारत ने 5 टी20 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती। सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय टी20 में सूर्यकुमार यादव ने छठी बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के मामले में सूर्यकुमार यादव श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट ने 7 बार ये उपलब्धि हासिल की है। फॉर्म में वापसी करने वाले सूर्यकुमार यादव जल्द ही विराट को पीछे छोड़ सकते हैं। सूर्यकुमार यादव ने तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए आखिरी टी20 में अपने 3,000 रन भी पूरे किए।

## हाफ मैराथन के आयोजन के लिए भारतीय नौसेना का धन्यवाद देना चाहती हूं: साइना नेहवालहाफ मैराथन के आयोजन के लिए भारतीय नौसेना का धन्यवाद देना चाहती हूं: साइना नेहवाल

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर नेवी प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पी. श्रीजेश उपस्थित थे। नेवी प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, 'भारतीय नेवी ने दूसरी बार हाफ मैराथन का आयोजन किया है। यह हमारा दिल्ली एडिशन था। हम मेजर स्टेशन पर लंबे समय से मैराथन का आयोजन करते रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अधिकारी और जवान न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और धार्मिक स्तर पर भी मजबूत बनें। दिल्ली एडिशन मैराथन से करीब एक लाख नेवी के जवाब फिटनेस को लेकर और जागरूक होंगे।' उन्होंने कहा कि पहले हाफ मैराथन में 10,000 से अधिक धावक एकत्रित हुए थे। इस बार करीब 13,500 से अधिक धावक एकत्रित हुए। इसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल थे। मुझे जानकारी दी गई कि सबसे उम्रदराज धावक की उम्र 87 वर्ष से ऊपर की थी। इसके अलावा मैंने कुछ बहुत छोटे बच्चों को भी देखा। सभी जोश के साथ दौड़ रहे थे। लगभग 24 देशों के 88 अंतरराष्ट्रीय धावकों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह भारतीय नेवी का हाफ मैराथन अंतरराष्ट्रीय हो गया है। नेवी प्रमुख ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने झंडा दिखाकर हाफ मैराथन की शुरुआत की। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सरकार भी फिटनेस के क्षेत्र में फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से बेहतर कार्य कर रही है।


स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रधान संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रीटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या सी-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव, मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com, पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं सपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा।